प्रभात

इस अंक में .....

★ *छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव बहिष्कार की रपट ...* 9
★ *माओ का लेख*
हर क्रान्ति में राजसत्ता का सवाल ही ... 12
★ *साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण और युद्ध के खिलाफ*
मुम्बई घोषणा 2004 ... 13
★ *छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों की हड़ताल -*
नेतृत्व की गद्दारी के चलते विफल ... 15

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्स वार] दण्डकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

वर्ष - 17 अंक - 1 जनवरी-मार्च 2004 सहयोग राशि - 10 रुपए

भाजपा का "फील गुड फैक्टर" (खुशहाली एहसास) ढोंगबाजी है !
सत्ता पर दोबारा कब्जा करने के लिए की जा रही तिकड़मबाजी है !!

आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करो !

गांव-गांव में जनता की राजसत्ता के अंगों (*जनता ना सरकार*) को कायम कर, उन्हें मजबूत बनाकर, उनका विस्तार करते हुए जनयुद्ध को दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाओ!

प्यारे लोगों !

फिर एक बार चुनावों का मेला लग चुका है। जल्द ही 14वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। हमारे देश को झूठी आजादी मिलने के बाद, 1952 से जारी चुनावों के सिलसिले में कई बार कांग्रेस को ही सत्ता का सुख भोगने का मौका मिला था। लेकिन पिछले आठ सालों से भाजपा के नेतृत्व वाला राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन) हमारे देश पर शासन करता आ रहा है। अब इस चुनावी दंगल में मुख्य रूप से सत्तारूढ़ भाजपा, जो फिर से सत्ता पर कब्जाने की कोशिश में है और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जो किसी भी तरह अपनी खोई हुई सत्ता को पाने की फिराक में है, आमने-सामने हैं। बाकी तमाम पार्टियां एक-दूसरे से लड़-झगड़ते हुए ही किसी भी तरह अवसरवादी गठबन्धन बनाने के चक्कर में हैं ताकि सत्ता में हिस्सा पाया जा सके। लेकिन आम जनता तो यह कहकर इन चुनावों के प्रति अपनी अनिच्छा और नाराजगी प्रकट कर रही है कि "कोई भी जीते मगर हमें क्या मिलने वाला है।" हालांकि जनता इस सचाई को दिन-प्रतिदिन भली भांति समझ रही है कि चुनावों से उसकी जिन्दगी नहीं बदलेगी और इस व्यवस्था में कोई बुनियादी फर्क नहीं आएगा, फिर भी वह किसी न किसी को वोट डाल रही है क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रही है कि इसका सही विकल्प क्या है। दूसरी तरफ पिछले 35 सालों से चुनाव बहिष्कार करने की वैकल्पिक क्रान्तिकारी राह पर भी जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 सालों से क्रान्तिकारी आन्दोलन के इलाकों में वर्तमान सड़ी-गली लुटेरी व्यवस्था की जगह पर जनता की राजसत्ता के अंगों (*जनतना सरकार*) का निर्माण चल रहा है जो अब संख्या और विस्तार की दृष्टि से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। **हम देशवासियों का आह्वान करते हैं कि आगामी ढोंगी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करके इस नए वैकल्पिक रास्ते पर आगे बढ़ें जिसे दण्डकारण्य के साथ-साथ आन्ध्र, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा आदि राज्यों की जनता ने ईजाद किया है।**

इन चुनावों की पृष्ठभूमि

दरअसल लोकसभा के चुनाव अभी नहीं होने वाले थे। 13वीं लोकसभा की मुद्दत अक्टूबर माह तक खत्म होनी थी। लेकिन भाजपा-नीत 24 पार्टियों के राजग ने लोकसभा को समय से पहले ही भंग करने का फैसला लेकर औपचारिक रूप से 6 फरवरी को भंग कर दिया क्योंकि उसे डर था कि आगे स्थिति ठीक होगी भी या नहीं। इसका एक मात्र कारण यह है कि हाल में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को उसके अनुमान से बढ़कर सफलता हाथ लगी थी जिससे वह यह निष्कर्ष पर पहुंच गई कि अब देश भर में उसके पक्ष में 'लहर' बन गई है। आगामी एक साल के भीतर देश के पांच अन्य राज्यों – महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम और उड़ीसा – में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में जहां राजग की घटक पार्टियां सत्ता में हैं, वहां विधानसभाओं को भंग करके तुरन्त चुनाव कराने की तैयारियां चल रही हैं क्योंकि वे इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती हैं। इनमें आन्ध्रप्रदेश मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू सबसे आगे है। पिछले अक्टूबर में पीजीए छापामारों ने उस पर हमला किया था जिसमें वह बाल-बाल बच गया। इस घटना के बाद

चन्द्रबाबू ने समय से पहले चुनाव कराने का फैसला लिया क्योंकि वह इस भ्रम में है कि उसके प्रति लोगों में हमदर्दी निर्मित हो गई है और उसका उसे फायदा मिल सकता है। दरअसल समय से पहले चुनाव कराने का फैसला करने वाली भाजपा और उसकी अन्य सहयोगी पार्टियां ''लहर'' के साथ ही जीतने की उम्मीद कर रही हैं न कि अपने किए काम के बल बूते पर।

चुनावी जोड़-तोड़ आए दिन नए-नए मोड़ ले रहे हैं। कौन किसके साथ हाथ मिलाने से कितना फायदा होगा, इसका हिसाब लगाते हुए गठजोड़ बनाए भी जा रहे हैं और टूट भी रहे हैं। चुनावी मैदान तैयार हो रहा है जिसमें भाजपा और कांग्रेस प्रमुख दावेदार होंगी। संशोधनवादियों ने यह कहकर हथियार डाल दिए कि तीसरे मोर्चे के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। सब अपने-अपने नारे लगाते हुए 'विकास' की रट लगा रहे हैं। भाजपा यह कहते हुए कि कांग्रेस अपने 50 सालों के शासन में जो नहीं कर सकी उसने सिर्फ 5 साल में करके दिखाया, यानी 50 बनाम 5 कहकर ढिंढोरा पीट रही है कि अब देश में ''फील गुड फैक्टर'' (खुशहाली एहसास) है और ''फील ग्रेट'' (बढ़िया एहसास) भी है। अटल को ऊंचा उठाते हुए विपक्ष की यह कहकर खिल्ली उड़ा रही है कि उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके। अटल संदेश यात्रा, रथयात्राएं, बस यात्राएं, विजयी यात्राएं, पैदल यात्राएं तेजी पकड़ रही हैं। भाजपा यह कहते हुए सोनिया गांधी पर हमला कर रही है कि इस देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है। अब चूंकि प्रियंका और राहुल के भी राजनीतिक मैदान में उतरने के आसार नजर आने लगे हैं तो उसने यह कहना भी शुरू किया कि इस देश के नागरिकों की संतान ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सकती है। उसने मुख्य रूप से मुध्यम वर्ग के मतदाताओं को रिझाने के लिए हाल ही में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा करों में कटौती कर दी। वह रोजाना एक नई योजना की घोषणा कर रही है। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वह रियायतों की बारिश कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस सक्षम नेतृत्व के अभाव में भाजपा के आक्रामक प्रचार का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सक रही है। वह सत्ता पर कब्जा करने के लिए हताशा भरी कोशिश कर रही है। कई राज्यों में अपनी चूल्हें हिल जाने से वह बेहद परेशान है। ऐसी स्थिति में भाजपा अगर दोबारा सत्ता पर काबिज हो भी जाती है तो वह विपक्ष की कमजोरी का नतीजा ही कहलाएगा न कि जनता की स्वीकृति का।

चुनावी दंगल में उतरने वाली सत्ता पक्ष या विपक्ष की कोई भी पार्टी जनता की बुनियादी समस्याओं को नहीं उठा रही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, चिकित्सा आदि जनता की बुनियादी समस्याओं को न तो कांग्रेस ने अपने 50 साल के शासन में हल किया था और न ही भाजपा ने अपने 5 साल के शासन में हल किया है। इस लुटेरी व्यवस्था के चलते इन समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, बल्कि वे गम्भीर रूप धारण कर रही हैं। **जब तक शासक वर्ग साम्राज्यवादियों के आदेशों का पालन करते रहेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठनों की जी-हुजूरी करते रहेंगे, तब तक असली विकास की कोई सम्भावना नहीं होगी। शासक वर्ग जिस 'विकास' की बात कर रहे हैं वह दरअसल लुटेरों का विकास ही है। अनगिनत जनता बेहद गरीबी में जिन्दगी गुजार रही है। इसलिए हम लोगों का आह्वान करते हैं कि ढोंगी 'विकास' की रट लगाते हुए वोट मांगने वाली चुनावी पार्टियों को मार भगाएं।**

क्या किसानों की आत्महत्याएं भी 'विकास' का ही हिस्सा हैं?

हमारा देश एक अर्ध औपनिवेशिक और अर्ध सामंती देश है। यहां पर 70 फीसदी लोग खेती-किसानी पर निर्भर करते हैं। लेकिन तथाकथित आजादी के 55 सालों बाद भी किसानों की बुनियादी समस्याओं का कोई हल नहीं हुआ है। किसानों की समस्या जमीन की समस्या ही है। लेकिन आज भी असली किसानों के हाथ में जमीन नहीं है। है भी तो थोड़ी-बहुत ही। हालांकि भूमि सुधार के कई कानून लाए गए, लेकिन वो सब कागजों में ही सिमटकर रह गए। खास तौर पर पिछले 15 सालों से साम्राज्यवाद-अनुकूल आर्थिक नीतियों को लागू करते हुए यहां की खेती-किसानी की बलि चढ़ाई जाने के कारण किसानों की जिन्दगी और भी बदतर बन गई। सारी सब्सिडियों (रियायतों) को हटा लिया गया। किसानों के द्वारा उगाई जा रही फसलों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। हालांकि गन्ना, कपास आदि फसलें उगाने वाले किसानों ने देश के कई हिस्सों में फसलों को समर्थन मूल्य की मांग करते हुए कई बार आन्दोलन चलाया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बिजली कटौती के कारण पैदावर कम होने से परेशान किसानों को सरकारें बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी करके 'शाक' दे रही हैं। खेती पर लागत काफी बढ़ चुकी है। उर्वरकों व कीटनाशक दवाइयों की कीमतें तथा पानी और ईंधन की कीमतें आए साल बढ़ती ही जा रही हैं। कृषि पूंजी और मूल्य आयोग की रिपोर्ट की मुताबिक वर्ष 1996-97 और 2001-02 के बीच बिजली और डीजल की कीमतों में धान के समर्थन मूल्य की तुलना में 40 फीसदी और गेंहू के समर्थन मूल्य की तुलना में 30 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है। दवाओं और बीजों की मुनाफाखोर कम्पनियां नकली उत्पाद बेचकर किसानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।

हमारे देश की खेती-किसानी का आज भी काफी हद तक बारिश पर निर्भर रहना 'विकास' का ढिंढ़ोरा पीटने वाले शासकों की घोर लापरवाही का एक जीता-जागता उदाहरण है। कई राज्य पिछले कई सालों से गंभीर सूखे से पीड़ित हैं। राजस्थान पिछले 4 सालों से, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पिछले 3 सालों से तथा आन्ध्रप्रदेश पिछले कई सालों से भयानक अकाल के चपेट में हैं। पिछले साल कुल 16 प्रदेश अकाल से पीड़ित थे तो राजग सरकार ने उनकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। **जहां एक तरफ सरकारी गोदामों में 6 करोड़ 20 लाख टन धान सड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, आदि राज्यों में लोग एक जून की रोटी न मिल पाने से भूख से तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। इससे दरअसल ''फील गुड'' नहीं, बल्कि ''फील भूख'' का ही संकेत मिल रहा है।**

कृषि क्षेत्र में साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की नीतियों के दुष्परिणामों के चलते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक (आंशिक) समेत, जहां पर बताया जाता है कि हरित क्रान्ति सफल हो चुकी है, कई राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। खुद को 'हाई टेक'

मुख्यमंत्री बताने वाले चन्द्रबाबू के शासनकाल में आन्ध्रप्रदेश में 3,500 किसानों ने खुदकुशी कर ली। इस कड़वी सचाई से यह अन्दाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि 'सूचना क्रान्ति' ने किसानों को क्या दिया है और अब 'किसान वाणी' और 'किसान काल सेन्टर' क्या दे पाएंगे, जिनका आज-कल लुटेरे नेता बढ़-चढ़कर प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में हैदराबाद शहर में अपनी केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके ''फील गुड फैक्टर'' कहकर प्रचार अभियान छेड़ देने वाली भाजपा क्या यह बता सकती है कि अगर सब कुछ ''फील गुड'' है तो उसके बगल में ही किसान बड़ी संख्या में क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं? सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक महाराष्ट्र के विदर्भ अंचल में पिछले तीन सालों में 175 किसानों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन जाहिर सी बात है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा। मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड इलाके में जहां एक तरफ कर्जों के बोझ से दबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई अन्य किसान रोटी नहीं मिल पाने से भूख से मर रहे हैं। **दरअसल किसानों की तमाम आत्महत्याएं और भुखमरियां सरकारी हत्याएं ही हैं।**

डब्ल्यूटीओ की शर्तें किसानों की जिन्दगी को और भी बर्बाद कर रही हैं। ये शर्तें इतनी अपमानजनक हैं कि सरकार जहां एक ओर अमेरिका के सूअरों के लिए 4.50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेंहू का निर्यात कर रही है, वहीं दूसरी ओर आयात किए गए गेंहू को उचित मूल्य दुकानों के जरिए 6.50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रही है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जहां एक तरफ अपने-अपने देशों में कृषि क्षेत्र को लाखों करोड़ों डॉलर की सब्सिडियां दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे डब्ल्यूटीओ के जरिए गरीब देशों पर दबाव लाकर सब्सिडियां समाप्त करवा रहे हैं। जनता के विरोध के डर से हमारे देश के शासक वर्ग दबी आवाज में यह मांग कर रहे हैं कि अमीर देश सब्सिडियां देना बन्द करें। लेकिन वे इस डब्ल्यूटीओ, जिसमें शामिल रहना देश की सम्प्रभुता के लिए ही अपमान है, से पूरी तरह बाहर आकर खुद अपने पैरों पर खड़े होकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। ऊपरी तौर पर साम्राज्यवाद को चुनौती देने के अंदाज में दिखने वाले भारतीय शासक वर्ग वास्तव में साम्राज्यवाद के, खासतौर पर अमेरिकी साम्राज्यवाद के वफादार गुलाम का ही काम कर रहे हैं। **भाजपा के ''फील गुड फैक्टर'' को झूठ का पुलिन्दा साबित करने के लिए सिर्फ यह एक उदाहरण काफी है कि हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 50 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक गिर चुका है।**

इसलिए हम किसानों से अपील करते हैं कि इन लुटेरे वर्गों की झूठी घोषणाओं से धोखा मत खाएं और वोट मांगने वाली पार्टियों को मार भगा दें। **किसानों के सामने एक ही रास्ता बचा है कि वे देश के कई हिस्सों में जारी हथियारबन्द कृषि क्रान्ति में शामिल होकर ''जमीन उसकी जो उसे जोते'' के नारे से लड़कर हमारे देश को साम्राज्यवाद और सामंतवाद के बन्धनों से मुक्त करें।**

नई आर्थिक नीतियों के दुष्चक्र में फंसा मजदूर वर्ग

1991 से हमारे देश में नई आर्थिक नीतियों के नाम से उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नीतियों पर अमल शुरू हो चुका है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इनकी शुरूआत की तो मौजूदा भाजपा सरकार इन पर दृढ़ता से अमल कर रही है। 1999 में जब तत्कालीन वित्त मंत्री यश्वन्त सिन्हा ने दूसरी किश्त के आर्थिक सुधारों को शुरू किया था, तब से इनका अमल सभी क्षेत्रों में बढ़ गया है। इन नीतियों के फलस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। 1991 में रोजगार केन्द्रों में अपना नाम दर्ज करवाने वाले बेरोजगारों की संख्या 3.5 करोड़ थी, जबकि वह अब 4.5 करोड़ हो गई। इनके अलावा ग्रामीण इलाकों के बेरोजगारों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा होगी। भूमण्डलीकरण की नीतियों के तहत सरकार द्वारा लागू मजदूर विरोधी नीतियों के चलते लाखों मजदूर अपना रोजगार खो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, रेलवे विभाग में मजदूरों की संख्या 22 लाख से 14 लाख तक घट गई। वर्ष 1998-2002 के बीच अलग-अलग उद्योगों में काम बन्द कर दिए जाने से 60 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लान्ट में एक समय एक लाख मजदूर हुआ करते थे, जबकि उनकी संख्या अब 40 हजार तक घट गई। और कई उद्योगों में तालबन्दी के नाम पर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नाम पर, छंटनी के नाम पर और डाउनसाइजिंग के नाम पर मजदूरों को नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कई कम्पनियों को पानी के मोल बेच देने से भी हजारों मजदूर सड़कों पर फेंक दिए गए।

राजग ने यह यकीन दिलवाया था कि अगर वह सत्ता में आएगा तो सालाना एक करोड़ लोगों को नौकरियां देगा। हाल ही में उसने यह घोषणा की कि वह एक करोड़ न सही, सालाना 84 लाख लोगों को तो नौकरियां दे रहा है। लेकिन एक ओर लाखों लोगों को नौकरियों से निकाल कर और संगठित क्षेत्र में कई नौकरियों को हमेशा के लिए खत्म कर रोजगार के अवसरों को बेहद घटाते हुए नौकरियां देने की बात करना जनता के साथ धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। 1999 में हमारे देश के संगठित क्षेत्र के सरकारी और निजी कम्पनियों में कर्मचारियों की संख्या 2.89 करोड़ थी जो अब 2.77 करोड़ से भी कम हो गई। क्या सालाना 84 लाख लोगों को नौकरियां देने का दावा करने वाला वाजपेयी के पास इसके लिए है कोई जवाब? सच यह है कि सरकार जो नौकरियां देने की बात कर रही है उनमें से ज्यादातर तो ऐसी हैं जिनमें सुबह नियुक्ति की जाती है और शाम तक बरखास्तगी भी की जाती है। और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो नौकरियां देने की बात की जा रही है, वे दरअसल यहां इसलिए आई हैं क्योंकि साम्राज्यवादी अपने खर्च को कम करने के लिए अपनी कम्पनियों के क्रियाकलापों को गरीब देशों में स्थानान्तरित कर रहे हैं जहां लोग सस्ती मजदूरी पर मिलते हैं। ये नौकरियां ऐसी हैं जब चाहे तब ये यहां से जा भी सकती हैं। इन्हें और इसी तरह की कुछ अन्य चीजों को दिखाते हुए भाजपा ''फील गुड'' वाला प्रचार जोर-शोर से कर रही है। दरअसल इस प्रचार के लिए सरकार जो सैकड़ों करोड़ों रूपए का जनता का धन पानी की तरह खर्च कर रही है, उसे अगर वह उत्पादन के क्षेत्र में लगाती है तो हजारों लोगों को स्थाई तौर पर पक्का रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता था।

नौकरियां गंवाने, कर्जों के बोझ से दबने और रोजगार न मिलने से निराश मजदूरों की आत्महत्याओं की घटनाएं हमें भूमण्डलीकरण का दिया हुआ एक और 'तोहफा' हैं। मुम्बई स्थित टाटा बिजली कम्पनी में काम करने वाले अनन्त दल्वी और अख्तर खान ने पिछले

अक्टूबर माह में आत्महत्या कर ली। इन्हें काम से अवैध ढंग से निकाला गया था तो इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अदालत ने फैसला इन मजदूरों के पक्ष में ही सुनाया, फिर भी कम्पनी के मालिकों ने फैसले को लागू नहीं किया। इससे निराश होकर इन दोनों ने यह कदम उठाया। ऐसी घटनाएं देश भर में कई जगहों पर आए दिन घट रही हैं।

शासक वर्ग एक ओर मजदूरों की जिन्दगी से इस प्रकार खिलवाड़ करते हुए ही दूसरी ओर हड़ताल करने का उनका न्यूनतम अधिकार भी हड़पने की साजिश कर रहे हैं। हाल ही में तमिलनाडु में दो लाख हड़ताली कर्मचारियों को जयाललिता की फासीवादी सरकार द्वारा बरखास्त किया जाना और उसके तुरन्त बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मजदूरों की हड़ताल को अवैध ठहराते हुए फैसला दिया जाना इसकी दो उदाहरण हैं। हालांकि बूर्जुवाई और संशोधनवादी ट्रेड यूनियन कभी-कभार निजीकरण की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान तो कर रहे हैं, पर वे एक बड़ी साजिश के तहत ही आन्दोलन को डटकर और मजबूती से न चलाकर बीच में ही गद्दारी कर रहे हैं या फिर आन्दोलन को सरकारी दमन का शिकार बनवा रहे हैं। वे अपने ''संघर्ष'' के जरिए मजदूरों को सीधे तौर पर यह समझा रहे हैं कि लड़कर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। **दरअसल सचाई यह है कि सभी पार्टियां भूमण्डलीकरण की नीतियों को लागू करने में राजग का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग ही कर रही हैं।**

इसलिए अब फौरी जरूरत इस बात की है कि मजदूर वर्ग यह तय कर ले कि उसे इस लुटेरी व्यवस्था को जड़ से बदलने वाले संघर्ष में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना है या फिर शासक वर्गों द्वारा अमल साम्राज्यवाद-अनुकूल लुटेरी नीतियों का शिकार बनते रहना है। **मजदूर वर्ग को तभी असली मुक्ति मिल सकती है जब वह लुटेरे वर्गों की चुनावी नौटंकी का बहिष्कार करके देश में आन्ध्र, बिहार-झारखण्ड, दण्डकारण्य, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आदि इलाकों में जारी नव जनवादी क्रान्ति में शामिल होगा।**

शिक्षा के बाजारीकरण से नौजवानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़

तीन साल पहले संविधान में संशोधन के जरिए आवश्यक प्राथमिक शिक्षा को लागू करने के बाद ''सभी को शिक्षा'' कहकर शासक वर्ग भले ही बढ़-चढ़कर प्रचार कर रहे हों, लेकिन कड़वी सचाई यह है कि हमारे देश में साक्षरता दर आज भी 58 प्रतिशत का आकंड़ा पार नहीं की। यह दर बेहद गरीब अफ्रीकी देश सूडान की दर से बराबर है। महिलाओं में यह दर 40 फीसदी से भी कम है। कई देशों में शिक्षा पर रक्षा बजट के बराबर खर्च किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में शिक्षा पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 3.98 प्रतिशत ही है। नई आर्थिक नीतियों के तहत प्राथमिक शिक्षा समेत सभी स्तरों पर शिक्षा का निजीकरण बड़ी तेजी से जारी है। शिक्षा एक लाभदायक धंधा बन गया। निजी विश्वविद्यालय कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे हैं। फीस में बढोत्तरी, मुफ्त सीटों को पैसे में बेचना, आदि से गरीब व मध्यम वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करना असम्भव होता जा रहा है। सरकारी विद्यालयों की हालत कछुए की चाल से भी बदतर हो गई है। सरकारें छात्रों को न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा रही हैं। छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। अगर कोई नियुक्ति हो रही है तो सिर्फ अस्थाई आधार पर ''शिक्षा कर्मियों'' या ''शिक्षा गारन्टी गुरूजियों'' के रूप में ही हो रही है। स्थाई आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति लगभग बन्द हो गई है। शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कहने में कोई आश्चर्य नहीं है कि इनका काम बेगारी मजदूरों से भी बदतर है। विश्व बैंक से बड़े पैमाने पर कोश लाकर जोर-शोर से नई-नई योजनाएं शुरू करके बाद में उन्हें बीच में बन्द कर देना सरकारों की नीयत सी बन गई है। पढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं हैं और पढ़े-लिखे होने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। युवाओं का भविष्य एकदम अंधकार में है। ऐसी स्थिति में तेजी से फल-फूल रही साम्राज्यवादी विशृंखल संस्कृति से प्रभावित होकर कई नौजवान समाज-विरोधी तत्वों, अपराधियों, दलालों और वेश्याओं में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन राजग सरकार तो इन कठोर सचाइयों पर परदा डालते हुए ''शाइनिंग इंडिया'' (भारत उदय) का राग आलाप रही है।

नौजवान इस देश की आंखें और पैर हैं। देश का भविष्य पूरा उन्हीं के हाथों में है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनके सपने क्यों पूरे नहीं हो पा रहे हैं। समाज की तमाम बीमारियों के लिए जिम्मेदार सामंतवाद, दलाल पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को ध्वस्त करने के लिए जारी नव जनवादी क्रान्ति में भाग लेने के अलावा उनके सामने कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। **हम देश के नौजवानों का आह्वान करते हैं कि वे वोट मांगने आने वाली लुटेरी पार्टियों को ठुकरा दें और ''फील गुड'' की आड़ में तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने वाली भाजपा को बेनकाब कर दें।**

देशवासियों की अनमोल सम्पदाओं को औने-पौने दामों में बेचना ही भाजपा का कथित 'विकास'

नेहरू के जमाने की मिश्रम अर्थव्यवस्था के दिन अब लद चुके हैं। सब कुछ निजीकरण करने और जनता की सम्पदाओं को मनमाने ढंग से बेचने की प्रक्रिया जो 1991 में शुरू हुई थी अब भाजपा के शासनकाल में हदें पार कर गई है। जनता की सम्पदाओं को इस तरह पानी के मोल बेचने के लिए विशेष रूप से एक मंत्रालय (विनिवेश विभाग) को ही खोलने का ''श्रेय'' भाजपा को ही जाता है। संघ गिरोह की मातृ संस्था आरएसएस एक ओर 'स्वदेशी जागरण मंच' की आड़ में देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विरोध करते हुए ही दूसरी ओर भाजपा के जरिए 'विनिवेश' के लिए अलग से एक मंत्रालय ही बनवाया। इससे बड़ा ढोंग और कहीं देखने को नहीं मिलता। यह सारा नाटक इसलिए किया जा रहा है जो लोग थोड़ी-बहुत देशभक्ति रखते हैं और संघ गिरोह की राजनीति पर यकीन करते हैं उनके लिए 'स्वेदेशी जागरण मंच' के नाम से एक मंच मुहैया करवाया जाए ताकि उन्हें संघ की शोषणकारी राजनीति से जोड़े रखा जा सके। ये लोग कोका कोला, पेप्सी जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हमारे देश से मार भगाने का प्रयास नहीं करते जो हमारे देश की जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। एक तरफ जनता की अनमोल सम्पदाएं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सुपुर्द करवाई जा रही हैं तो ये लोग

इस प्रक्रिया को रोकने की कोई सार्थक प्रयास नहीं करते। यही है इनकी 'स्वदेशी' नौटंकी!

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के लिए सारे दरवाजे खोलने वाले शासक वर्गों ने उन्हें कई रियायतें दे रहे हैं। कोका कोला, पेप्सी जैसी अमेरिकी कम्पनियों को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सैकड़ों करोड़ों रुपए की रियायतों के फलस्वरूप हमारे देश के सैकड़ों बाटिलिंग कम्पनियां बन्द पड़ गईं। कई छोटे व मध्यम पूंजीपतियों का दिवालिया निकल गया। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के नाम पर महानगरों में मौजूद कई छोटे व मध्यम उद्योगों को बन्द करवाकर लाखों मजदूरों और हजारों देशीय पूंजीपतियों के पेट पर लात मारने वाली सरकार साम्राज्यवादियों की कम्पनियों द्वारा पर्यावरण को व्यापक नुकसान पहुंचाए जाने के बावजूद भी चुप्पी साध रही है। हाल ही में कोक और पेप्सी के शीतल पेयों में घातक कीटनाशकों के अवशेष पाए जाने की एक रिपोर्ट प्रकाश में आई थी जिस पर देशवासियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इन कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जिससे हमारे देश के शासक वर्गों के दलाल चरित्र फिर एक बार नंगे तौर पर सामने आ गया।

भाजपा की केन्द्र सरकार ने 2001 में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्यवान बाल्को कम्पनी को सिर्फ 551 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसी प्रकार 2,200 करोड़ रुपए की कीमत वाले माडर्न फुड्स की सिर्फ 150 करोड़ में नीलामी करवाई। 80 हजार करोड़ रुपए की कीमत के महाराष्ट्र बिजली बोर्ड को सिर्फ 30 हजार करोड़ रुपए में बेचने की कोशिशें जारी हैं। सभी राज्य सरकारें इसी नीति पर चलते हुए बिजली बोर्डों और परिवहन संस्थाओं को निजी कम्पनियों को बेच डालने की प्रक्रिया में जुटी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में एक नदी को भी सरकार ने बेच दिया। इसके पहले विपक्षी पार्टियां सतही तौर पर ही सही, ऐसी जन-विरोधी कार्यवाहियों का विरोध किया करती थीं। यहां तक कि नई आर्थिक नीतियों का प्रणेता कांग्रेस ने भी भाजपा द्वारा बाल्को की बिक्री के मौके पर और कुछ दूसरे मौकों पर दिखावटी ही सही, विरोध किया था। लेकिन अब रुझान बदल गया। अब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां यह कहते हुए कि निजीकरण की प्रक्रिया हमने ही शुरू किया है, एक-दूसरे से लड़-झगड़ रही हैं। इस प्रकार ये दोनों पार्टियां अपनी गद्दारी को छिपाने की साजिश कर रही हैं जो वे देशवासियों के साथ कर रही हैं

हाल के महीनों में भाजपा ने ''फील गुड फैक्टर'' के नाम से जो प्रचार अभियान शुरू किया उसका आधार भी मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में हुई कथित 'वृद्धि' ही है। लेकिन भाजपा के सारे दावे आंकड़ों की तिकड़मबाजी के अलावा कुछ भी नहीं हैं। दरअसल सचाइयां बिलकुल दूसरी ही कहानी बयान कर रही हैं। भाजपा यह कहते हुए ढिंढ़ोरा पीट रही है कि उसके शासन के दौरान देश में विदेशी मुद्रा भण्डार में 100 अरब डॉलर जमा हो चुके हैं। लेकिन यह देश के निर्यातों से जुटाया गया धन नहीं है। न तो निर्यातों में हुई बढ़ोत्तरी से और न ही विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश में कोई उल्लेखनीय प्रगति से जमा होने वाले इस धन को देखकर विकास कहना बिलकुल नादानी ही है। इस धन में ऐसे डॉलर भी हैं जो हमारे देश में ब्याज की दरें अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज की दरों के मुकाबले ज्यादा होने और सोने के दाम में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप यहां पहुंचे हैं। इसी को 'हॉट मनी' कहा जाता है जो रातोंरात कहीं और भी चला जा सकता है। अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि की बात जो बताई जा रही है वह दरअसल अनुत्पादक क्षेत्र में हुए विकास पर ही आधारित है। 11 सितम्बर की घटनाओं के बाद औंधे मुंह गिर चुके सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब थोड़ी-बहुत तेजी आने जैसे अस्थाई कारणों से 'विकास' की जो धुंधली तस्वीर नजर आ रही है वह न तो असली है और न ही टिकाऊ है। भाजपा यह नहीं बताती कि जब चारों तरफ ''खुशहाली'' ही है तो देश में भुखमरियां लगातार क्यों हो रही हैं। वह इसका कारण भी नहीं बताती कि देश में लगातार कई सालों से अकाल और सूखे की स्थिति क्यों निर्मित हो रही है। वह इस सवाल का जवाब भी नहीं बताती कि हाल के सालों में ही किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। वह इस सचाई पर परदा डालने की कोशिश करती है कि हमारे देश का विदेशी कर्ज 5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। बेरोजगारी का जिक्र वह भूलकर भी नहीं करती। भाजपा ने आंकड़ों को तोड़-मरोड़ करके जनता को भ्रम में रखते हुए प्रचार अभियान इसलिए छेड़ दिया ताकि आगामी चुनावों में किसी भी तरह दोबारा जीत हासिल की जा सके। इसके लिए उसने सुनियोजित ढंग से ''मिशन 2004'' शुरू किया। केन्द्र सरकार ने इस झूठ-मूठ के 'विकास' को बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करने के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए का जनता का धन खर्च किया। एक अनुमान के मुताबिक फरवरी के पहले सप्ताह तक ही इस प्रचार पर सरकार ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है वहां पर वह ''100 दिनों का एजेन्डा'', ''एक महीने का एजेन्डा'' आदि नामों से कई सस्ती चालें चल रही है ताकि मतदाताओं में भ्रम फैलाकर उन्हें रिझाया जा सके।

देश के हितों को लेकर चिन्तन-मनन करने वाले तमाम लोगों को शासकों की साजिशों और तिकड़मों को समझने की जरूरत है। **हमारे देश में असली विकास तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि यहां से साम्राज्यवादियों और उनके दलालों को मार भगाकर अपने पैरों पर खड़े होने वाली एक नई आर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता। असली विकास उसी व्यवस्था में मुमकिन होगा जिसमें सभी को रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मानजनक रोजगार, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाएं मिलें और जिसमें शोषण व उत्पीड़न के लिए कोई जगह ही न हो।** आज की सख्त जरूरत है कि लुटेरे शासक वर्गों के खिलाफ जारी जनयुद्ध में आप सब शामिल हो जाएं ताकि असली विकास को हासिल किया जा सके। इस मौके पर हम तमाम देशभक्त लोगों से अपील कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करें और ग्रामीण इलाकों को केन्द्र बनाकर जारी जनयुद्ध से नाता जोड़कर नई व्यवस्था के निर्माण के लिए कमर कर लें।

जन आन्दोलनों पर फासीवादी भाजपा का कसता शिकंजा

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू साम्राज्यवाद-अनुकूल आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप जनता को कई कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन नीतियों के खिलाफ सभी तबकों के

लोग आन्दोलन चला रहे हैं। जनता के संघर्षों को कुचलने में भाजपा ने अपनी तमाम पूर्ववर्ती सरकारों को पछाड़ दिया है। एक समय कांग्रेस ने 'टाडा' जैसे बर्बर कानून लाया था तो अब भाजपा ने उससे दस गुना ज्यादा खतरनाक और गैर-जनवादी कानून 'पोटा' लाया। लेकिन जब कांग्रेस ने टाडा कानून लाया था, तब भाजपा ने उसका विरोध किया था। डब्ल्यूटीसी और पेन्टागन पर हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका द्वारा प्रारम्भ ''विश्व व्यापी अभियान'' में राजग सरकार बढ़-चढ़कर भाग ले रही है। कश्मीरी जनता के कत्लेआम लगातार व बिना रुके जारी है। अब तक 80 हजार कश्मीरी लोग सरकारी हत्याकाण्ड का शिकार हो गए। वहां वर्ष 2002 में सम्पन्न चुनावों में सरकार द्वारा चलाए गए व्यापक दमनकारी अभियानों, कत्लेआम और चुनावी धांधलियों के बावजूद अत्यधिक लोगों ने चुनावों का बहिष्कार किया था। लेकिन सरकार ने जनता पर चलाए गए दमनचक्र पर परदा डालते हुए यह प्रचार किया कि कश्मीर में चुनावों से लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है।

पूर्वोत्तर भेत्र के कई राष्ट्रीय आन्दोलनकारी संगठनों को शांतिवार्ता के नाम से गुमराह करने और उन्हें निष्क्रिय बनाने में भी भाजपा को एक हद तक सफलता मिली है। भाजपा जहां एक ओर लड़ाकू संगठनों को निष्क्रिय बनाने की कोशिशों के साथ-साथ झूठे विकास के कार्यक्रम लागू कर रही है, वहीं दूसरी ओर लड़ाई जारी रखने वालों का सफाया करने की नीति भी लागू कर रही है। हाल ही में राजग सरकार ने भूटान सरकार के साथ हाथ मिलाकर उल्फा जैसे मिलिटेन्ट संगठनों पर हमला करवाकर सैकड़ों लोगों की हत्या करवाई।

राजग सरकार क्रान्तिकारी आन्दोलन पर व्यापक दमनचक्र चला रही है। नक्सलवादी आन्दोलन से प्रभावित नौ राज्यों को मिलाकर ज्वाइंट ऑपरेशनल कमान्ड का गठन किया गया। इसके तहत पुलिस अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बार-बार बैठकें करते हुए जी-तोड़ कोशिशें कर रही है ताकि क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया किया जा सके। जिन राज्यों में भाजपा या राजग की घटक पार्टियां सत्ता में हैं, उन सरकारों को भाजपा की अगुवाई वाली केन्द्र सरकार मुंह मांगे पैसा, आदि सहायता कर रही है। इधर भाजपा ने एक बड़ी साजिश के तहत यह दुष्प्रचार करना शुरू किया कि कांग्रेस ने नक्सलवादियों के साथ सांठगांठ कर ली। पिछले दिसम्बर में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के मौके पर भाजपा ने यह दुष्प्रचार किया था और फिलहाल आन्ध्रप्रदेश में तेलुगुदेशम इस प्रकार कर रही है। वे जनता की तमाम बुनियादी समस्याओं को ताक पर रखकर नक्सलवाद और आतंकवाद को बहुत बड़े खतरे के तौर पर पेश करते हुए अपनी दमनात्मक कार्यवाहियों को वैधता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ चलाए जाने वाले पाशविक फासीवादी दमन और कत्लेआम को स्वीकृति हासिल करने की मंशा से ही शासक वर्ग इस प्रकार कोशिश कर रहे हैं। वे इस सचाई पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जनता की बुनियादी समस्याओं का हल न होने के कारण ही अलग-अलग उठ आन्दोलन खड़े हो रहे हैं। नक्सलवाद को ऊपरी तौर पर कभी-कभार सामाजिक-आर्थिक समस्या कहने वाले शासक वर्ग वास्तव में तो उसे कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में ही देखते हुए दमनचक्र चला रहे हैं। सरकार नक्सलवादी आन्दोलन से प्रभावित हर राज्य को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बटालियन गठन करने में सहायता करने का फैसला लिया। झूठी मुठभेड़ें, गिरफ्तारियां, महिलाओं पर अत्याचार, आदि का सिलसिला आन्दोलन के इलाकों में अंधाधुंध चल रहा है। खासतौर पर आन्ध्रप्रदेश में चन्द्रबाबू सरकार भाजपा के समर्थन से मनमाने कत्लेआम मचा रही है। चन्द्रबाबू के शासन में पुलिस ने 1,475 क्रान्तिकारियों, हमदर्दों और आम लोगों को मार डाला। शासक वर्ग क्रान्तिकारियों और उनके समर्थकों को अपनी फासीवादी अदालतों के जरिए भी दंडित कर रहे हैं। बिहार और झारखण्ड में सामंती उत्पीड़कों के खिलाफ जनता द्वारा किए गए वीरतापूर्ण हमलों के मामलों में कुछ लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। शासक यह सपना देख रहे हैं कि वे इस प्रकार सजाएं देकर किसानों को सामन्ती उत्पीड़न और दमन के तले दबाकर रख सकेंगे। इस सबके बावजूद भी देश के कई हिस्सों में जनता मजबूती से लड़ रही है। हमारी पार्टी भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] और हमारी बिरादराना पार्टी एमसीसीआइ की अगुवाई में संगठित होकर जनता की राजसत्ता कायम करने की दिशा में दृढ़तापूर्वक कदम बढ़ा रही है।

भाजपा के शासन में चरम पर पहुंचा हिन्दू साम्प्रदायिकतावादी उन्माद

2002 में गुजरात में हुआ अमानवीय कत्लेआम भारत के इतिहास में ही एक कलंक के तौर पर रह जाएगा। देश के बंटवारे के समय हुए कत्लेआमों और अत्याचारों को भुला देते हुए संघ गिरोह द्वारा सुनियोजित ढंग से चलाए गए इस नरसंहार में कम से कम 2,500 मुसलमान मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। कई महिलाओं के साथ समूहिक बलात्कार करके मानवता सारी सीमाएं तोड़ दी गईं। गोधरा में मुसलमानों ने एक रेल में आग लगाकर संघ गिरोह के कार्यकर्ताओं को जिन्दा जला दिया – इस बहाने संघ गिरोह ने बड़े सुनियोजित ढंग से इस कत्लेआम को अंजाम दिया। मौजूदा व्यवस्था कितनी फासीवादी बन चुकी है, इसका अंदाजा इस सचाई से लगाया जा सकता है कि इस जघन्य नरसंहार में नरेन्द्र मोदी के मत्रीमण्डल के कई मंत्रियों, पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सीधे तौर पर भाग लिया। भगवा रंग के कपड़े पहने हुए त्रिशूलधारी गुण्डों ने कई मसजिदों, ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों को तोड़ दिया।

ईसाई लोगों, उनके गिरिजाघरों, पादरियों और सन्यासिनों पर गुजरात समेत कई अन्य राज्यों में हमले किए गए। उड़ीसा में ग्राहम स्टाइन्स और उनके दो बेटों को जिन्दा जलाकर मार डालने वाला हत्यारा दारा सिंह विश्व हिन्दू परिषद का एक कार्यकर्ता था। संघ गिरोह मध्यप्रदेश के भोजशाला, कर्नाटक के बाबा बुढानगिरी आदि जगहों पर भी मुसलमानों के प्रार्थनास्थलों को तबाह कर हिन्दू मंदिर बनाने के लिए लोगों को उकसा रहा है। दोनों धर्मों के लोगों के बीच नफरत की आग फैलाने की कोशिश कर रहा है।

हिन्दुत्व एजेन्डे को ताक पर रखने और राजग के साझे एजेन्डे पर ही चलने का दावा करने वाली भाजपा अपने हिन्दुत्व एजेन्डे को भी सुनियोजित रूप से आगे बढ़ा रही है। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को नहीं उठाने की बात करने वाले भाजपा नेता अलग-अलग मौकों पर यह घोषणा भी कर रहे हैं कि वे राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। चुनावी प्रचार अभियान का बिगुल बजाते हुए वाजपेयी ने भी एक ताजे बयान में राम मंदिर का निर्माण करने का वायदा किया। भाजपा जनता की मनोभावनाओं का अंदाजा लगाकर जब-तब बात बदलते हुए और परस्पर विरुद्ध व्याख्याएं करते हुए सुनियोजित ढंग से देश में धार्मिक

उन्माद भड़का रही है।

आदिवासियों पर संघ गिरोह के हमले बढ़ गए। विभिन्न आश्रमों द्वारा आदिवासियों को हिन्दुओं में बदलने की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर जारी है। संघ की शाखाएं और उसके कार्यकर्ता कोने-कोने में जाकर हिन्दुत्ववाद के लिए एक मजबूत आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके आदिवासियों को ललचाकर "घर वापसी" के नाम से फिर से हिन्दू धर्म में खींच रहे हैं। किसी भी धर्म से न जुड़ने वाले आदिवासियों को हिन्दू बताते हुए गलत टिप्पणियां कर रहे हैं।

फासीवाद को व्यवस्थीकृत बनाने की बहुत बड़ी साजिश के तहत पाठ्यांशों में मौजूद धर्मनिरपेक्ष भावनाओं को हटाकर हिन्दुत्व की भावनाएं शामिल कर छात्रों को पाठशाला के कमरों से ही अंधराष्ट्रवादी तैयार करने की कोशिशें जारी हैं। जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है वहां ये कोशिशें खुलकर की जा रही हैं, जबकि कांग्रेस की ढोंगी धर्मनिरपेक्षता और संशोधनवादी पार्टियों की नरम धर्मनिरपेक्षता की बदौलत अन्य राज्यों में भी ये कोशिशें किसी न किसी रूप में चल रही हैं। इतिहास को तोड़-मरोड़कर दोबारा लिखा जा रहा है। पाठ्यांशों से प्रगतिशील साहित्य को हटाया जा रहा है। राजग सरकार ने इतिहास कांग्रेस समेत सभी अहम अकादमिक संस्थाओं से धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील विचारों वाले लोगों को हटाकर संघ गिरोह के समर्थकों को नियुक्त किया है। इस तरह भाजपा एक तरफ फासीवाद को व्यवस्थीकृत करने की कोशिशें करते हुए ही दूसरी तरफ अपने गुण्डों और शिवसैनिकों का इस्तेमाल करते हुए पाशविक हमले भी करवा रही है। हाल ही में पूने के एक ग्रंथालय पर किया गया हमला, कुछ साल पहले चित्रकार एमएफ हुस्सेन की प्रदर्शनी पर किया गया हमला, कुछ फिल्मों की शूटिंग को रोकने की घटनाएं जिनकी कहानी संघ गिरोह को पसन्द न थी – इस तरह के कई उदाहरण गिनाए जा सकते हैं।

भाजपा द्वारा अमल हिन्दू फासीवादी नीतियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी साम्राज्यवाद की मदद हासिल है। दक्षिण एशिया में जूनियर सरदार के रूप में उभरने के भारत के दलाल शासक वर्गों की तमन्नाओं का भाजपा प्रतिनिधित्व कर रही है। दक्षिण एशिया के जन आन्दोलनों और क्रान्तिकारी आन्दोलनों के लिए भारतीय विस्तारवाद एक बड़ा खतरा बन चुका है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में माओवादियों के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध का दमन करने के लिए भारत सरकार वहां की प्रतिक्रियावादी राजशाही सरकार की हर प्रकार की सहायता कर रही है। एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ पिछले पांच सालों में वह कई बार युद्ध करते-करते रह गई। पाकिस्तान का खौफ दिखाते हुए हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी सैन्य क्षमता में जबर्दस्त इजाफा कर रही है। अमेरिका के वफादार गुलामों की तरह काम कर रहे भारत और पाकिस्तान का बारम्बार एक-दूसरे से लड़-झगड़ना और अगले ही पल दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना हाल के महीनों में जैसे एक प्रहसन ही बन गया। सचाई यह है कि साम्राज्यवादी इन दोनों देशों के शासकों की चोटियों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर बंदर नाच नचवा रहे हैं ताकि इन दोनों देशों के बाजारों को अपनी पकड़ में रखा जा सके। इन देशों में व्याप्त संकट के चलते दोनों ही देशों की शोषित जनता बेहद परेशान है। दोनों देशों के लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में अवर्णीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जनता में बढ़ रहा यह असन्तोष कहीं सामाजिक क्रान्ति का रूप न ले, इसके लिए इन दोनों देशों के शासक वर्ग अपने-अपने देशों के लोगों को एक-दूसरे पर उकसा रहे हैं।

भाजपा के शासन में बेहद बढ़ चुके हिन्दू फासीवाद के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। असली धर्मनिरपेक्षतावादियों, प्रगतिशील विचारों वाले लेखकों और बुद्धिजीवियों पर हमले हो रहे हैं। **इसलिए देश के तमाम जनवाद-पसन्द और धर्मनिपेक्षतावाद-पसन्द लोगों तथा अल्पसंख्यक धर्मों के लोगों और आदिवासियों को एकजुट होकर एक विशाल मंच पर आने की सख्त जरूरत है।** इस मौके पर हम आपसे अपील करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनावों का एकमत से बहिष्कार करके देश में जारी नव जनवादी क्रान्ति में शामिल हो जाएं और ऐसी नई व्यवस्था के निर्माण के लिए आगे आएं जिसमें सभी राष्ट्रीयताओं को समान अधिकार हों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत हो और जिसमें जाति उत्पीड़न और सभी किस्म की असमानताओं और भेदभावों का अन्त हो।

चनावों का बहिष्कार करके 'जनताना सरकार' संस्थाओं का निर्माण कर, उन्हें मजबूत बनाते हुए जनयुद्ध को नए स्तर तक आगे बढ़ाना ही असली विकल्प!

अभी तक कई बार चुनाव हो चुके हैं, कई मंत्री, प्रधानमंत्री आए और गए हैं। हर पार्टी को कभी न कभी किसी न किसी हद तक सत्ता का सुख मिल चुका है। सत्ता पर काबिज होने के बाद हर नेता ने अनगिनत भ्रष्टाचार-घोटालों के जरिए जनता का धन लूटने का ही काम किया है। खुद को "क्लीन" पार्टी कहकर भाजपा चाहे कितना भी ढिंढ़ोरा पीट ले, लेकिन ताजातरीन जूदेव काण्ड में लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी 'स्वच्छता' में कितनी सचाई है। कांग्रेस के शासन में बोफोर्स घोटाला, हवाला घोटाला, प्रतिभूति घोटाला, यूरिया घोटाला आदि प्रमुख घोटाले थे तो पिछले पांच सालों में भाजपा के शासन में ताबूत घोटाला, रक्षा विभाग की खरीदियों का घोटाला, तहलका घोटाला, पेट्रोल पम्प घोटाला और ताजातरीन जूदेव रिश्वत काण्ड व स्टैम्प पेपर घोटाला रोशनी में आए। कई अन्य घोटालों पर हमेशा के लिए परदा डालकर उन्हें रोशनी में नहीं आने दिया गया। लेकिन जनता को भूख, अकाल, गरीबी, बेरोजगारी, आत्महत्याएं – यही नसीब हुए। इसलिए जनता को यह जरूर सोचना चाहिए कि कई बार वोट डालने के बावजूद भी हमारी जिन्दगी क्यों नहीं बदली है और हमारी बुनियादी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा है।

हमारे देश में सामंती और दलाल पूंजीवादी वर्गों के लोग ही शासन चला रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, जनतादल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगुदेशम, डीएमके, अन्ना डीएमके – ये सारी पार्टियां उपरोक्त लुटेरे वर्गों के अलग-अलग गिरोहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें साम्राज्यवादियों, खासतौर पर अमेरिकी साम्राज्यवादियों का समर्थन हासिल है। लाल झण्डा की आड़ में खुद को छिपाने वाली भाकपा, माकपा, भाकपा (मा-ले लिबरेशन) जैसी नकली कम्युनिस्ट पार्टियों की तो बातों में ही कुछ फर्क लगता है, लेकिन व्यवहार में इनके और उपरोक्त अन्य लुटेरी पार्टियों में कोई फर्क नहीं

है। इस तरह ये सारी चुनावी पार्टियां शोषक पार्टियां ही हैं। सब चोर-चोर मौसेरे भाई जैसे ही हैं। इनमें से चाहे किसी को भी वोट देने से इस व्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। कोई भी जीते तो हमारी जिन्दगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी तब तक इन चुनावों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम जनता से कह रहे हैं कि इस लुटेरी व्यवस्था को और उसके तमाम अलग-अलग अंगों को जड़ से बदलने के लिए क्रान्ति के अलावा कोई चारा ही नहीं है। यह क्रान्ति तभी होगा जब जनता खुद हथियारबन्द बनकर अपनी एक सेना बना लेगी। हमारे देश में यह क्रान्ति दीर्घकालिक रास्ते पर होगी जिसमें ग्रामीण अंचलों को मुख्य कार्य-क्षेत्र बनाकर इलाकावार राजसत्ता पर दखल करते हुए देश भर में फैल जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सामंतवाद, दलाल पूंजीवाद और इनका साथ देने वाले साम्राज्यवाद का सफाया करके मजदूर-किसानों की एकता के आधार पर छोटे और मध्यम पूंजीपतियों के सम्मेलन से बनने वाला संयुक्त मोर्चा अपने हाथों में राजसत्ता ले लेगा। यह राज अत्यधिक मेहनतकश लोगों के लिए असली लोकतंत्र के रूप में तथा मुट्ठी भर लुटेरों के लिए तानाशाही के रूप में होगा। जनता अपने प्रतिनिधियों को आजादी के साथ चुन लेगी। सिर्फ चुनने का अधिकार ही नहीं, बल्कि अपना वोट वापस लेकर चुने गए प्रतिनिधि को वापिस बुलाने का अधिकार भी जनता को होगा यदि वह समझती है कि अमुक प्रतिनिधि सही ढंग से काम नहीं कर रहा/रही है। इस जनवादी तरीके में जनता की राजसत्ता के निर्माण की प्रक्रिया आज हमारे दण्डकारण्य में तेजी से जारी है। कई गांवों में शोषक शासक व्यवस्था के स्थान पर मेहनतकश लोगों की साझी राजसत्ता की संस्था के रूप में "*जनताना सरकार*" (जन सरकार) का गठन हो चुका है। कई अन्य गांवों में इन संस्थाओं का फैलाव हो रहा है। इन संस्थाओं का विस्तार करके समूचे दण्डकारण्य में जनता की राजसत्ता की स्थापना करने, यानी दण्डकारण्य को मुक्त इलाके में बदलने के लक्ष्य से आज यहां जनयुद्ध आगे बढ़ रहा है। **हमारे दण्डकारण्य में जारी जन संघर्ष और यहां पर भ्रूण रूप में पनप रही जनता की राजसत्ता आज समूचे देश की जनता के लिए एक आदर्श और एक नमूने के रूप में विकसित हो रहे हैं। तमाम देशवासियों के लिए अनुसरणीय मार्ग के रूप में उभर रहे हैं।**

लेकिन शासक वर्ग यहां की जनता की राजसत्ता को जब वह पौधा हो तभी जड़ से मिटाने के इरादे से गंभीर कोशिशें कर रहे हैं। हजारों पुलिस बलों को उतारकर हमारे आन्दोलन का दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। लुटेरे शासक वर्ग पाशविक दमनचक्र चलाकर आन्दोलन को खून की नदियों में डुबाने के लिए कमर कसे हुए हैं। पिछले दिसम्बर माह में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के मौके पर बस्तर अंचल में युद्ध का माहौल बनाया गया था। सैन्य हेलिकाप्टरों के जरिए गगनतल से गश्त लगाई गई। इसके बावजूद जनता ने जनयुद्ध को दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाया। चुनावों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया। पीजीए छापामारों ने कई प्रतिरोधी कार्यवाहियां करके सीआरपी बलों की नींदें उड़ाकर रख दीं। किसी भी तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाकर दिखाने का निश्चय कर चुके सरकारी व पुलिस अधिकारियों ने कई गांवों में आए बिना ही खुद ही वोट डालकर चुनाव की रस्म पूरी कर दी। कई अन्य मतदान केन्द्रों में अत्यधिक लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया तो बाकी का काम मतदान कर्मियों ने ही पूरा करके मतदान प्रतिशत को बढ़ा दिया। इसी को सरकार ने 'बुलेट पर बैलेट की जीत', 'नक्सलियों के चुनावों के बहिष्कार का नारा विफल" आदि सुर्खियां लगाकर प्रचारित किया। लेकिन सचाई क्या है यह दण्डकारण्य की जनता को अच्छी तरह मालूम है। हम जनता से अपील कर रहे हैं कि इन लोकसभा चुनावों का भी पिछले अनुभवों के आधार पर दृढ़तापूर्वक बहिष्कार किया जाए। **हम इस मौके पर जन छापामार सेना के लाल योद्धाओं और बहादुर कमाण्डरों का आह्वान करते हैं कि चुनावों का बहिष्कार करने के जनता के जनवादी अधिकार का हनन करते हुए जुल्म और हिंसा का प्रयोग करने वाले सरकारी सशस्त्र बलों का मजबूती से मुकाबला करें तथा जनता की मदद में डटकर खड़े रहें।**

- ***झूठे चुनावों का बहिष्कार करके गांव-गांव में "जनताना सरकार" का निर्माण करते हुए उन्हें मजबूत करो !***
- ***जन छापामार सेना की अगुवाई में पुलिस के पाशविक दमनचक्र का साहस के साथ प्रतिरोध करो !***
- ***लुटेरी व्यवस्था को तबाह करके जनता की जनवादी व्यवस्था कायम करने के लिए जनयुद्ध को तेज करो !***
- ***हिन्दू फासीवादी गिरोहों को तहस-नहस करो ! हिन्दू धार्मिक कट्टरतावादी भाजपा को कड़ा सबक सिखा दो !***
- ***सभी चुनावी पार्टियां बड़े जमींदारों और बड़े पूंजीपतियों की हिफाजत करने वाली चोर-लुटेरों की पार्टियां हैं ! वोट मांगने आने वाली लुटेरी पार्टियों को मार भगाओ !***
- ***मुट्ठी भर चोर-लुटेरों का विकास नहीं है "फील गुड" – जिस दिन तमाम जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आदि सब कुछ मिल जाएंगे उसी दिन होगा असली "फील गुड" !***
- ***नव जनवादी क्रान्ति जिन्दाबाद !***

क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ ...

स्पेशल जोनल कमेटी

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार]

दण्डकारण्य

दिनांक : 20 फरवरी 2004

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों का बहिष्कार रपट

पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों के पाशविक दमन का डटकर मुकाबला करते हुए

बस्तर की जनता के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों का बहिष्कार

विगत नवम्बर-दिसम्बर महीनों में देश के पांच राज्यों – दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए। 1 नवम्बर 2000 को गठित नया राज्य छत्तीसगढ़ में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण बस्तर, उत्तर बस्तर, बस्तर और सरगुजा इलाकों की जनता को आतंकित करके मतदान कराने का फैसला किया। खासकर चुनावी प्रहसन को पूरा करवाकर संसदीय व्यवस्था में जान फूंकने का प्रयास किया। इसलिए बस्तर इलाके के उत्तर बस्तर, माड़, पश्चिम बस्तर, दक्षिण बस्तर डिवीजनों के दन्तेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर जिलों सहित सरगुजा के कुछ इलाकों को नक्सली प्रभावित क्षेत्र घोषित करके हमारे संघर्ष इलाकों में स्थित बीजापुर, कोंटा, नारायणपुर, भानुप्रतापपुर, केसकाल विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों को सरकार ने अति संवेदनशील घोषित किया। हजारों की संख्या में सीआरपीएफ, बीएसएफ, जिला पुलिस एवं एसएएफ बलों को तैनात किया। 'शांतिपूर्ण', 'स्वेच्छापूर्ण' तथा 'निष्पक्ष' चुनावों के नाम पर 137 कम्पनियों के अर्ध सैनिक बलों तथा भारतीय वायुसेना के 35 हेलिकाप्टरों का इस्तेमाल किया। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में इस तादाद में सशस्त्र बलों को तैनात नहीं किया गया। फर्जी विधानसभा चुनावों के संचालन के लिए इस इलाके को केन्द्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने रणभूमि में तब्दील किया। फर्जी चुनावों का बहिष्कार करने वाली जनता पर एवं जनता के पक्ष में डटे पीजीए के तीन बल – जन मिलिशिया, माध्यमिक तथा मुख्य बलों पर आसमान से हेलिकाप्टरों की निगरानी तथा गन फायर, जमीन पर पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों की अंधाधुंध गोलीबारी, दो इंच मोर्टार द्वारा गोलाबारी, ग्रेनेड लांचरों का इस्तेमाल करके सरकार ने ही आतंक का माहौल पैदा करके फर्जी चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया।

फर्जी विधानसभा चुनावों में मुख्य बुर्जुवा पार्टियां कांग्रेस एवं भाजपा ने जनता से तरह-तरह के वायदे किए। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार किया एवं भोले-भाले आदिवासियों को आकर्षित करने के लिए असफल प्रयास किया। उम्मीदवारों ने जन धन को पानी की तरह बहाया। फिर भी इनका प्रचार नारायणपुर, कोंटा, भानुप्रतापपुर, दोरनापाल, कोइलीबेड़ा, भोपालपटनम, बीजापुर आदि विकासखण्ड, तहसील एवं पुलिस जिला मुख्यालयों तक ही सीमित रहा। माड़ के पहाड़ों पर स्थित गांवों, किष्टारम, बासागूडा, ऊसूर, नेशनल पार्क, मिरतुल, गंगलूर आदि ग्रामीण इलाकों, कोइलीबेड़ा, रावघाट, चारगांव, डौला इलाकों के गांवों में चुनाव प्रचार का नामोनिशान तक नहीं था। हालांकि पुलिस का गश्त अभियान जारी था। जन संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार करके यातनाएं दी गई थीं। लेकिन कोई भी चुनावी पार्टी अंदरूनी इलाकों में आने या वोट मांगने का साहस नहीं कर सकी। कुछ हाइवे चौराहों पर स्थित बड़े गांवों में पुलिस की सुरक्षा में चुनावी सभाएं संचालित की गईं एवं पोस्टर चिपकाए गए। कुछ विकासखण्ड केन्द्रों में तो ये पार्टियां मतदान कार्यालय भी खोल नहीं सकीं। अंदरूनी गांवों के मुखियाओं, सरपंचों, पटेलों, सचिवों आदि जन विरोधियों को इकट्ठा करके रुपए-पैसे एवं दारू दिए गए। मुख्य सड़कों पर स्थित गांवों और विकासखण्ड केन्द्रों के नजदीकी गांवों को चुनकर 'बकरा-भात' के नाम पर दावत दी गई एवं दारू बहाया गया। वोट नहीं डालने पर गांवों पर पुलिस के द्वारा हवाई बमबारी करने, मकानों में आग लगाने, महिलाओं पर अत्याचार करने एवं जान से मारने का लगातार प्रचार किया गया। बाद में इस प्रचार को सही साबित भी किया गया। स्थानीय सरकारी अमला, पुलिस, बुर्जुवा एवं संशोधनवादी पार्टियों के नेता तथा मुखिया लोग मिलकर हमारे खिलाफ यह दुष्प्रचार किया कि नक्सली विकास विरोधी हैं, जनवाद विरोधी हैं, हिंसावादी हैं तथा आतंकवादी हैं। स्थानीय समाचार पत्रों ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर प्रकाशित किया। क्रान्तिकारी आन्दोलन के इलाके से अपरिचित लोग इस झूठे प्रचार से आसानी से दिग्भ्रमित हो सकते हैं। चुनाव प्रचार के लिए जगदलपुर आए प्रधानमंत्री वायपेयी ने भी नक्सलियों को बस्तर के विकास में बाधा बताई। भाजपा नेताओं ने अपने भाषण में यह ऐलान किया कि वे यदि सत्ता में आएंगे तो पोटा कानून को लागू करेंगे। बस्तर रेंज का आईजी संत कुमार पाशवान नक्सलियों के खिलाफ हर दिन अखबारों में बयान देता था। भाजपा ने पार्टी पर यह झूठा आरोप लगाया कि नक्सली नेताओं ने कांग्रेस के साथ सांठगांठ करके कांग्रेसी नेताओं से लाखों रुपए का चंदा लिया है। जनता के बीच क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रति गलतफहमियां पैदा करने कई तरह का झूठा प्रचार किया।

विधानसभा चुनावों के 9 महीनों पहले ही, मार्च 2003 में ही केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के तीन बटालियन नक्सली आंदोलन के सफाए के लिए तैनात किए गए। इसके अलावा जोगी सरकार ने शांतिपूर्ण चुनाव के नाम पर हजारों की तादाद में अर्ध सैनिक बलों को मंगवाया। नवम्बर तक उन्हें संघर्ष इलाकों में तैनात किया। पड़ोसी राज्यों के पुलिस बलों के साथ मिलकर संयुक्त गश्ती अभियान चलाया गया। दमन और उन्मूलन शुरू किया। गांव में गश्त अभियान बढ़ाते हुए लोगों को गिरफ्तार करना, जांच-पड़ताल करना, फर्जी मुकदमों में जेल भेजने के अलावा कुछ गांवों में अंधाधुंध फायरिंग भी किए। महिलाओं पर अत्याचार किए। ऐसे इलाकों में जहां पीजीए के सशस्त्र बलों ने सरकारी सशस्त्र बलों का मुकाबला किया हो, पुलिस अत्याचारों का कोई हिसाब नहीं। उदाहरण के लिए उत्तर बस्तर डिवीजन के कोइलीबेडा के पास स्थित जरंतराय के समीप हमारे पीजीए बलों ने अर्ध सैनिक बलों पर हमला किया था। इस हमले को बहाना बनाकर पास के खेतों में काम कर रहे दो किसानों को लाकर गोली मारकर मुठभेड़ की कहानी गढ़ी गई। पश्चिम बस्तर डिवीजन के भैरमगढ़ इलाके के गांव हरित के पास मिलिशिया के साथ हुई मुठभेड़ से बौखलाई पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की जिससे एक किसान महिला की जांघ में गोली लगी।

इस तरह समूचे बस्तर में विधानसभा चुनावों के पहले ही सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। नक्सलियों की पतासाजी के नाम पर किसानों के अलावा शिक्षकों, कर्मचारियों, व्यापारियों, चिकित्सकों, आखिर स्थानीय पुलिस वालों, यहां तक कि एक-दो थानेदारों को भी सीआरपी बलों की हिंसा का शिकार होना पड़ा। हिंसा एवं क्रूरता का पर्याय बने सीआरपी बलों ने संघर्ष इलाकों के जनता पर अनगिनत अमानवीय अत्याचार किए। पूरे चुनाव के दौरान लोगों को जंगल जाने से, रिश्तेदारी में, हाट बाजार में, खेत-खार में जाने से वंचित किया गया। इस शोषणमूलक संसदीय जनतंत्र पर और चुनावी प्रक्रिया पर जिन्हें विश्वास नहीं है, उन्हें चुनाव बहिष्कार करने की स्वेच्छा एवं अधिकार से न केवल वंचित किया गया, बल्कि उन पर बन्दूकें तान दीं गईं। हेलिकाप्टरों की गश्त, पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों की संगीनों के साये 'जनवाद' के नाम पर चुनावी नौटंकी आखिरकार तीन दिसम्बर को समाप्त हुई।

विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का प्रचार अभियान

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने बस्तर में चुनाव बहिष्कार का आह्वान करते हुए अखबारों में बयान जारी किया एवं साक्षात्कार दिए। इससे समूचे दण्डकारण्य, यानी बस्तर के चारों डिवीजनों में दमन का मुकाबला करते हुए सितम्बर महीने से ही चुनाव बहिष्कार का प्रचार अभियान चालू हुआ।

माड़ डिवीजन

माड़ डिवीजन में स्थानीय सीएनएम (चेतना नाट्य मंच), जन संगठनों की 10 रेंज कमेटियों एवं 10 प्रचार दस्तों ने, यानी लगभग 100 लोगों ने एक सप्ताह तक चुनाव-बहिष्कार प्रचार किया। दो दफे हुए प्रदर्शनों एवं सभाओं में 20 हजार लोगों ने भाग लिया। सैकड़ों बैनर बांधे। पोस्टर चिपकाए। दीवार-लेखन भी की। पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों के दमन के विरोध में माड़ डीवीसी के आह्वान पर लोगों ने पूरे डिवीजन में दो दिनी बन्द का आयोजन किया (30 नवम्बर और 1 दिसम्बर)। चुनाव बहिष्कार के प्रचार के तहत मिलिशिया ने भी कुछ जगहों में हथियारबन्द प्रदर्शन किए। जन संगठनों के कार्यकर्ता घर-घर जाकर मतदाताओं से मतदान बहिष्कार की अपील की। डिवीजन की पत्रिका 'भूमकाल' विशेषांक प्रकाशित करके बड़े पैमाने पर जनता में बांटा गया।

उत्तर बस्तर डिवीजन

चुनाव बहिष्कार का प्रचार डिवीजन में तीन चरणों में हुआ। रैलियां एवं आम सभाएं हुईं। बड़े पैमाने पर पर्चे बांटे गए, पोस्टर चिपकाए गए, बैनर बांधे गए। प्रचार दस्तों ने समूचे डिवीजन में प्रचार किया। केएएमएस एवं डीएकेएमएस के 300 महिला एवं पुरुषों के 25 प्रचार दस्तों के अलावा 10 बच्चों का एक बालक दस्ता, 3 सीएनएम दस्तों तथा सभी स्थानीय छापामार दस्तों ने चुनाव बहिष्कार का प्रचार किया। सड़कों के चौराहों पर दीवार-लेखन की गई। पूरे डिवीजन में 1,300 पोस्टर चिपकाए गए एवं 74 बैनर बांधे गए। एक सवारी बस में भी बैनर बांधा गया। फर्जी चुनाव का पर्दाफाश करते हुए डिवीजनल कमेटी ने अखबारों को बयान जारी किया। चुनाव बहिष्कार की रैलियों एवं सभाओं में 25 हजार से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया। स्थानीय पत्रिका 'बेरा' को चुनाव बहिष्कार विशेषांक के रूप में प्रकाशित करके बड़े पैमाने पर बांटा गया।

पश्चिम बस्तर डिवीजन

बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के चार विकासखण्डों – ऊसूर, पटनम, भैरमगढ़ और बीजापुर में चुनाव बहिष्कार का प्रचार बड़े पैमाने पर तीन महीने चलाया गया। सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर महीनों में रैलियां आयोजित की गईं। स्थानीय एवं डिवीजन सीएनएम दस्तों के द्वारा आयोजित चुनाव बहिष्कार की सभाओं में 16 हजार लोगों एवं जन संगठनों के द्वारा आयोजित सभाओं में 33 हजार लोगों ने भाग लिया। हर सभा एवं प्रदर्शन में "फर्जी चुनावों का बहिष्कार करो", "सरकारी दमन को परास्त करो", "छापामार युद्ध को तेज करो", "जनताना सरकार कमेटियों को संगठित करो एवं उन्हें जनता के सही राजसत्ता के अंगों के रूप में विकसित करो" आदि नारों के द्वारा पार्टी के राजनीतिक संदेश को जनता में ले जाया गया। इसके अलावा दीवार-लेखन, 2100 पोस्टर एवं 65 बैनर बांधे गए। 5,000 पर्चे बांटे गए। इन सबके द्वारा विकासखण्ड मुख्यालयों, सड़कों पर स्थित गांवों, बाजारों, मेलाओं में प्रचार किया गया। बुर्जुवा संसदीय पार्टियों के नेताओं के पुतले जला दिए गए। सरकारी रेडियो एवं बुर्जुवा पत्र-पत्रिकाओं को भी हमारे चुनाव बहिष्कार के बारे में जनता को बताना पड़ा। समूचे डिवीजन में डीएकेएमएस के 84, केएएमएस के 31 प्रचार दस्तों ने दो दफे बहिष्कार का अभियान चलाया। इन दस्तों में कुल 600 लोग शामिल हुए। डिवीजनल कमेटी की ओर से चुनाव बहिष्कार का बयान जारी करने के साथ-साथ पत्रकारों को साक्षात्कार भी दिया गया। दक्षिण एवं पश्चिम बस्तर डिवीजनों की संयुक्त पत्रिका 'पितूरी' का चुनाव विशेषांक प्रकाशित करके जनता में बड़े पैमाने पर बांटा गया।

दक्षिण बस्तर डिवीजन

इस डिवीजन के कोंटा एवं बीजापुर विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के चार इलाकों – पामेड, जेगुरगोंडा, किष्टारम एवं कोंटा में चुनाव बहिष्कार का प्रचार सितम्बर से शुरू किया गया। चुनाव बहिष्कार के प्रचार के तहत डीएकेएमएस के 63, केएएमएस के 23 दस्तों के अलावा 27 लोगों को डिवीजन तथा स्थानीय सीएनएम दस्तों, 150 लोगों के 15 गांव स्तर के सीएनएम दस्तों ने सांस्कृतिक प्रदर्शनों और भाषणों के द्वारा गांवों एवं बाजारों में प्रचार किया। इतना ही नहीं, रेंज स्तर पर कुछ जगहों पर आमसभाओं को आयोजित किया गया। पूरे डिवीजन में कुल 366 गांवों में प्रचार किया गया। 2,000 पर्चे, 400 पोस्टर तीन चरणों में चिपकाए गए। 75 बैनर बांधे गए। 50 ऑडियो कैसेट वितरित किए गए। 100 गांवों में दीवार लेखन किया गया। सवारी बसों और अन्य वाहनों में पोस्टर चिपकाए गए, बैनर बांधे गए, नारे लिखे गए। इस तरह विभिन्न रूपों में चुनाव बहिष्कार का संदेश एक लाख लोगों तक पहुंचाया गया।

आग बरसते दमन का मुकाबला करते हुए फर्जी चुनावों का बहिष्कार

1 दिसम्बर को विधानसभा चुनाव होने वाले थे। लेकिन नवम्बर के दूसरे सप्ताह तक ही हजारों की संख्या में खाकी बल नारायणपुर, जगदलपुर, दन्तेवाडा, बीजापुर एवं कोंटा पहुंच गए। गांवों में गश्त करना, गिरफ्तारियों के साथ दमन एवं उन्मूलन अभियान चलाना शुरू किया। दक्षिण बस्तर के एर्रबोर, पश्चिम बस्तर के नेलसनार, जांगला में पुलिस चौकियां खोली गईं। चुनाव के दौरान कुछ गांवों की शालाओं एवं आश्रमों में अड्डा लगाकर एक-एक जगह एक-एक

कम्पनी के पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों को तैनात किया गया। उदाहरण के लिए माड़ के पहाड़ों पर गारपा, सोनपुर, आकाबेड़ा, कुडिमेर; पश्चिम बस्तर के केरपे, सेंड्रा में इस तरह तैनात किए गए सशस्त्र बलों ने आसपास के गांवों में भी गश्त अभियान चलाया। हेलिपैड का निर्माण करके मतदान दलों एवं पुलिस बलों को मतदान केन्द्रों तक पहुंचाया गया। आश्रमों में रहते समय छात्र-छात्राओं को, सफर के दौरान जनता को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। विधानसभा चुनावों में हासिल इन अनुभवों से सीख लेते हुए 14वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान कई गांवों की जनता पुलिस से बचने पहले ही गांवों से चली गई। इसे पुलिस ने तोड़-मरोड़कर उलटा प्रचार किया कि नक्सली गांवों को खाली करा रहे हैं।

विधानसभा चुनावों में मतदान के संचालन के लिए माड़ में 40 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए। इनमें से 10 केन्द्रों में लोगों ने पूरी तरह मतदान का बहिष्कार किया। 20 केन्द्रों में पुलिस ने डरा-धमकाकर कुछ लोगों से वोट डलवाया। बाकी 10 केन्द्र चूंकि पुलिस थाने, विकासखण्ड तथा तहसील मुख्यालय भी थे, इसलिए मतदान प्रतिशत कुछ ज्यादा ही रहा। यानी माड़ के कुल 300 गांवों में से 75 गांव मतदान से दूर रहे। 150 गांवों में बहुत कम, यानी 5-10 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि 75 गांवों में कुछ ज्यादा यानी 25 प्रतिशत मतदान हुआ। लेकिन बस्तर के कलेक्टर शैलेश पाठक ने यह दुष्प्रचार किया कि नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार की जनता ने अवहेलना की और बड़े पैमाने पर मतदान किया। 14वीं लोकसभा चुनावों से कुछ दिन पहले भी कलेक्टर ने यह झूठा प्रचार किया कि नक्सली हिंसा से डरकर कुछ गांवों की जनता गांव छोड़कर भाग गई। दरअसल आदिवासी जनता फसल कटाई के लिए खेतों में जाती है, दिन में घरों में नहीं रहती है। आदिवासी जन जीवन से अनजान कलेक्टर ने इसे बहाना बनाकर अफवाह फैलाने की असफल कोशिश की। कुछ मतदान केन्द्रों तक पुलिस पहुंची भी नहीं। कुछ और मतदान केन्द्रों में सीआरपीएफ बल ही वोटिंग मशीनों के बटन दबाकर मतदान को 80 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। उदाहरण के लिए कच्चापाल और गट्टाकल मतदान केन्द्रों तक पुलिस पहुंची ही नहीं, लेकिन 80 प्रतिशत होने की खबर छपी। जिला केन्द्रों एवं तहसील मुख्यालयों में भी इस कदर मतदान नहीं हुआ। 20 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आदिवासी जनता ने 80 प्रतिशत वोट डाला, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। दैनिक अखबारों ने ही इसे अविश्वसनीय करार दिया।

दक्षिण बस्तर डिवीजन में कुल 80 मतदान केन्द्रों में से 13 पुलिस थाने वाले गांवों में थे। और सड़क पर स्थित मतदान केन्द्र 18 थे। इन मतदान केन्द्रों को छोड़कर बाकी 45 केन्द्रों में जनता ने पूरी तरह मतदान का बहिष्कार किया। 10 गांवों में मिलिशिया एवं जन संगठन के कार्यकर्ताओं ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों को जब्त किया। इनमें से मात्र चार केन्द्रों में 3 दिसम्बर को दोबारा मतदान हुआ। बाकी जगहों पर आसमान में ही मतदान को 'सफल' बनाया गया।

पश्चिम बस्तर डिवीजन में कुल 95 मतदान केन्द्र हैं। इनमें से 30 केन्द्रों में पूरी तरह मतदान का बहिष्कार हुआ। 25 केन्द्रों में जो विकासखण्ड, तहसील मुख्यालय, पुलिस थाने वाले गांव हैं, पुलिस दमन के चलते जनता मतदान में शामिल हुई। बाकी गांवों में बहुत कम मतदान हुआ। 13 मतदान केन्द्रों में वोटिंग मशीनों को मिलिशिया एवं जन संगठन कार्यकर्ताओं ने जब्त किया। मात्र एक बीजापुर चुनाव क्षेत्र में ही 35 वोटिंग मशीनों को जब्त किया गया।

उत्तर बस्तर डिवीजन के करीब 250 गांवों में से 136 गांवों की जनता ने मतदान का बहिष्कार किया। बाकी गांवों में जो विकासखण्ड, पुलिस थाने, सड़क पर स्थित गांव हैं, पुलिस दमन के चलते जनता ने मतदान में भाग लिया। पूरे डिवीजन में नौ वोटिंग मशीनों को जब्त किया गया। दण्डकारण्य के चारों डीवीजनों में लगभग 100 मतदान केन्द्रों में पूरी तरह मतदान का बहिष्कार किया गया। सैकड़ों मतदान केन्द्रों में आंशिक तौर पर चुनाव बहिष्कार हुआ। मतदान या पुनरमतदान हुए गांवों में भी पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों के दबाव के चलते या उन्हीं के द्वारा बटन दबाकर किए गए मतदान से ही मतदान प्रतिशत बढ़ा दिया गया। जनता, मिलिशिया, पार्टी और जन छापामार सेना ने चुनाव बहिष्कार का प्रचार व्यापक रूप से किया एवं पूरे दण्डकारण्य में 55 वोटिंग मशीनों को जब्त किया। इस तरह हुए मतदान को बुलेट पर बैलट की जीत के रूप में चित्रित करते हुए पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों ने बुर्जुवा मीडिया में ढिंढोरा पीटा।

चुनाव के दौरान नवम्बर के दूसरे सप्ताह से ही जनता, जन संगठनों, मिलिशिया एवं जन छापामार सेना के सशस्त्र बलों ने संसदीय दलों के चुनाव प्रचार पर अंकुश लगाया। पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों पर हमले किए। पीजीए के तीनों बलों के द्वारा किए गए हमलों में दक्षिण बस्तर में सीआरपीएफ का एक जवान, पश्चिम बस्तर के मोदुगुपल्लि ऐम्बुश में जिला एवं एसएएफ के छह जवान मार डाले गए। उत्तर बस्तर में दो पुलिस वालों तथा एक गोपनीय सैनिक को मार डाला गया। एक दर्जन से भी अधिक पुलिस वालों को घायल किया गया। चुनाव के दौरान किए गए हमलों में सरकारी सशस्त्र बलों से एक एके-47 रायफल, 5 एसएलआर, 2 हथगोले, 340 कारतूस एवं एक वायरलेस सेट को जब्त किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर बस्तर में दो जीपों, पश्चिम बस्तर में एक टाटा सुमो, एक मोटर सायकिल, माड़ में सीपीएम वालों की एक जीप को आग के हवाले किया गया। दण्डकारण्य के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस, भाजपा के अलावा संशोधनवादी पार्टियां सीपीआइ, सीपीआइएम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन कोई भी उम्मीदवार संघर्ष इलाकों के अंदरूनी गांवों में आकर चुनाव प्रचार करने का साहस ही नहीं कर सका। जनता उनके वायदों और लालच का शिकार न होकर उनके प्रचार का विरोध किया। मतदान का बहिष्कार किया। तमाम जनता का भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) [पीपुल्स वार] क्रान्तिकारी अभिनन्दन करती है।

जन मिलिशिया सैकड़ों की संख्या में निकल पड़ी और पुलिस एवं अर्ध सैनिक बलों पर कई हमले किए। दो जगहों पर हेलिपैडों को ध्वस्त किया। सड़कों को अवरुद्ध किया। पीजीए के तीनों बलों ने मिलकर सिर्फ 1 दिसम्बर को ही 50 जगहों पर छोटे-बड़े हमले किए। हजारों की तादाद में तैनात सीआरपीएफ, सीआइएसएफ, बीएसएफ बलों के द्वारा जनवाद के नाम पर जनता पर अमल किया गया दमन, गिरफ्तारियां, यातनाएं, मोर्टार गोलाबारी, वायु सेना के हेलिकाप्टरों की गश्त एवं गन फायर के बीच बस्तर की जनता एवं पीजीए के तीनों बलों ने क्लेमोर बमों, भरमारों, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष और रायफलों से मुंहतोड़ जवाब देते हुए 3 दिसम्बर तक 130 से ज्यादा हमले किए। अस्थाई पुलिस कैम्पों पर हथगोले फेंके। पुलिस की आपूर्ति को कई जगहों पर रोक दिया। हमारी पार्टी दण्डकारण्य की जनता से अपील करती है कि जनयुद्ध के तहत दुश्मन के आतंकी बलों को परास्त करते हुए आगामी संसदीय चुनावों का बहिष्कार करे तथा 'फील गुड', 'भारत उदय' की बकवास का भण्डाफोड़ करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के झूठे प्रचार का पर्दाफाश करे। ❑

हर क्रान्ति में राजसत्ता का सवाल ही बुनियादी सवाल है ...

- कॉमरेड माओ

"हर क्रान्ति में राजसत्ता का सवाल ही बुनियादी सवाल है। अधिरचना की तमाम शाखाओं में भी – विचारधारा, धर्म, कला, न्यायशास्त्र और राजसत्ता – राजसत्ता ही केन्द्रीय सवाल है। सब कुछ राजसत्ता ही है। अगर वही नहीं है तो सब कुछ हाथ से छूट जाएंगे। इसलिए राजसत्ता को जीत लेने के बाद चाहे कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन सर्वहारा वर्ग को राजसत्ता को कभी भूलना नहीं चाहिए। उसे अपनी दिशा को कभी नहीं भूलना चाहिए। केन्द्रीय सवाल को अपनी नजरों से कभी ओझल नहीं होने देना चाहिए। राजसत्ता को भूलने का मतलब है राजनीति को भूलना और मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धान्त को भूलना। इसका मतलब अर्थवाद, अराजकवाद और काल्पनिक आदर्श राज की तरफ मुड़ जाना ही है। बेवकूफ बनना ही है। सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच सैद्धान्तिक मोर्चे में जारी वर्ग संघर्ष अन्तिम विश्लेषण में नेतृत्व के लिए जारी संघर्ष ही है। शोषक वर्ग जनता के द्वारा निहत्थे बना दिए गए। उनसे उनकी सत्ता छीन ली गई। लेकिन उनके प्रतिक्रियावादी विचार उनके दिमाग की परतों में जमे हुए हैं। हमने उनके शासन को उखाड़ फेंक दिया है। उनकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमने उनकी खोपड़ियों से प्रतिक्रियावादी विचारों को भी उखाड़ फेंक दिया है। शोषक वर्गों ने मेहनतकश जनता पर अपने हजारों सालों के शासन के दौरान अपनी प्रतिक्रियावादी राजसत्ता को मजबूत बनाने की खातिर मेहनतकश जनता द्वारा पैदा की गई संस्कृति पर एकाधिकार कायम करके, मेहनतकश जनता को धोखा देकर, बेवकूफ बनाकर, फिर उसी संस्कृति का इस्तेमाल किया ताकि उनके दिमाग को निष्क्रिय बनाया जा सके। हजारों सालों से उन्हीं की विचारधारा का बोलबाला जारी है। इसने समाज पर निश्चित रूप से व्यापक प्रभाव डाला है। अपने प्रतिक्रियावादी शासन के ढह जाने को न पचाते हुए वे जनमत को अपने अनुकूल मोड़ने के लिए इस प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि पूंजीवाद के राजनीतिक व आर्थिक पुनरुद्धरण के लिए तैयारियां की जा सकें। मुक्ति के दिनों से लेकर आज तक, जबकि 'तीन परिवारों के गांव' की कट्टर पार्टी-विरोधी और समाजवाद-विरोधी लाइन का पर्दाफाश किया गया हो, इन सोलह सालों में सैद्धान्तिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बिना रुके जारी संघर्ष पूरा उन विरोधी ताकतों के बीच संघर्ष ही है जो पुनरुद्धरण के लिए और पुनरुद्धरण के विरोध में खड़ी हैं।

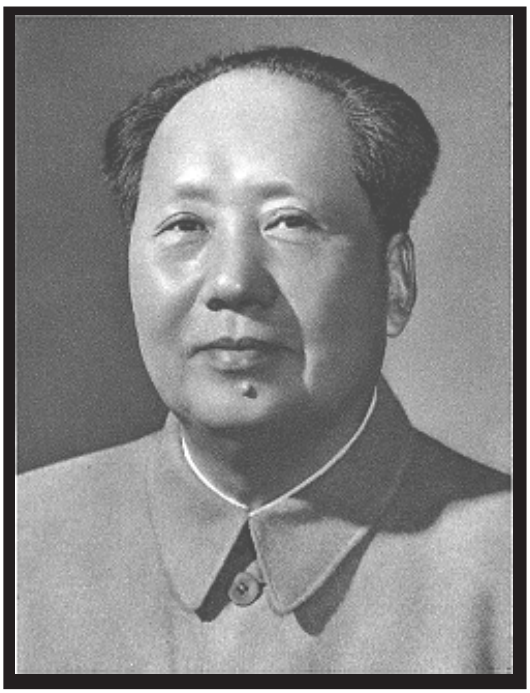

"पूंजीवादी क्रान्ति के दिनों में पूंजीपतियों ने भी ठीक इसी तरह से सांस्कृतिक क्रान्ति को शुरू करके सैद्धान्तिक तैयारियां शुरू की थीं, ताकि राजसत्ता पर कब्जा किया जा सके। एक लुटेरे वर्ग के स्थान पर दूसरे लुटेरे वर्ग को सत्ता में लाने वाली पूंजीवादी क्रान्ति को भी कई बार पीछे कदम डालना पड़ा था। कई संघर्ष झेलने पड़े थे – क्रान्ति, बाद में पुनरुद्धरण और फिर पुनरुद्धरण की समाप्ति। कई यूरोपियाई देशों को भी, सैद्धान्तिक तैयारियों से शुरूआत करने के बाद अन्तिम रूप से राजसत्ता जीत लेने तक अपनी-अपनी पूंजीवादी क्रान्तियों को पूरा करने में कई सैकड़ों साल लग चुके थे। चूंकि सर्वहारा क्रान्ति का मकसद सभी किस्म की शोषणकारी व्यवस्थाओं को जड़ से समाप्त करना है, इसलिए यह कल्पना ही नहीं करनी चाहिए कि शोषक वर्ग अपने शासन का पुनरुद्धरण का कोई प्रयास किए बिना यूं ही बकरों की तरह सर्वहारा वर्ग को यह इजाजत दे देंगे कि वह उनके सारे विशेषाधिकारों को समाप्त कर दे। इस परिणाम से नाखुश इन वर्गों के बचे हुए सदस्य, जैसा कि लेनिन ने बतलाया, अपने खोए हुए स्वर्ग को दोबारा हड़पने के लिए दस गुना ज्यादा गुस्से से जंग में कूद पड़ेंगे। कृश्चेव के संशोधनवादी गिरोह द्वारा सोवियत संघ में पार्टी, सेना और राज पर चोरी-छुपे से कब्जा एक ऐसी सचाई है जिससे समूचे सर्वहारा वर्ग को कड़ा सबक मिलता है। आज चीन में मौजूद पूंजीवादी प्रतिनिधि, पूंजीवादी 'पंडित' और 'अधिकारी' ठीक यही सपना देख रहे हैं कि पूंजीवाद का पुनरुद्धरण किया जाए। उनकी राजसत्ता भले ही ढहा दी गई हो, लेकिन वे अपने विद्वत्तपूर्ण 'सत्ता' को बनाए रखने के लिए जनमत को उभारने तथा लोगों, नौजवानों और उन पीढ़ियों को भी जिन्हें हमने अभी तक जन्म ही नहीं दिया हो, अपनी तरफ रिझाने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं।

"पूंजीवादियों द्वारा चलाई गई सामंतवाद-विरोधी सांस्कृतिक क्रान्ति तभी समाप्त हो गई जब उन्होंने सत्ता हथिया ली थी। लेकिन सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति सभी लुटेरे वर्गों की विचारधारा के खिलाफ सांस्कृतिक क्रान्ति है। यह सांस्कृतिक क्रान्ति पूंजीवादी सांस्कृतिक क्रान्ति से पूरी तरह भिन्न है। सर्वहारा वर्ग द्वारा राजसत्ता पर कब्जे के बाद जब आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पूर्व-शर्तें तैयार बन जाएंगी तभी सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के लिए एक विशालतम रास्ता खुल जाएगा। ❑

साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण और युद्ध के खिलाफ
मुम्बई घोषणा 2004

हम, "साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण और युद्ध के खिलाफ मुम्बई प्रतिरोध 2004", जो भारत के मुम्बई में 17-20 जनवरी के बीच आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय समारोह है, जिसमें भारत के कोने-कोने से और समूची दुनिया के कई अन्य देशों से आने वाले 300 से ज्यादा संगठनों और हजारों दूसरे शख़्सों ने भाग लिया, यहां पर निम्नांकित घोषणा को पारित करते हैं।

हमने एमआर 2004 (मुम्बई प्रतिरोध 2004) के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। इसकी कल्पना जून 2003 में थेस्सालोनिकि प्रतिरोध (Thessaloniki Resistance) में जन संघर्षों का अन्तर्राष्ट्रीय लीग (आइएलपीएस - इंटरनेशनल लीग ऑफ पीपुल्स स्ट्रगल्स) ने की थी कि एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन समारोह का आयोजन किया जाए जो कि विभिन्न साम्राज्यवाद-विरोधी संगठनों द्वारा प्रायोजित हो ताकि साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन को सगठित और शक्तिशाली बनाया जा सके।

एकता, प्रतिबद्धता, ऊर्जा और अन्तर्राष्ट्रीय तालमेल, जिन्हें एमआर 2004 ने इकट्ठा किया, पैदा किया और बढ़ा दिया है, से प्रेरणा और ताकत पाते हुए हम निम्नलिखित शपथें लेते हैं और कार्यवाही का आह्वान करते हैं:

हम साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण और युद्ध के खात्मे तक लड़ने की शपथ लेते हैं। इसके लिए हम उन तमाम ताकतों के साथ एकताबद्ध हो जाएंगे जो इस नए जन विरोधी आक्रमण के नतीजे में पैदा हो रहे संत्रासों के खिलाफ खड़ी हुई हैं।

हम गरीबी में फंसे हुए उन जन समुदायों के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़े होने की शपथ लेते हैं जो साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण का बुरी तरह शिकार हैं। हम साम्राज्यवादी लूट-खसोट और युद्ध के खिलाफ दुनिया भर में जारी संघर्षों में उनके साथ एकताबद्ध हो जाएंगे।

हम समाज पर विनाशकारी प्रभावों का मजबूती से विरोध करने की शपथ लेते हैं जो अमानवीय गरीबी, जनता की जीविका की तबाही, पर्यावरण की तबाही, संवेदनरहित उपभोक्तावाद, उन्नत विमुखीकरण और जनता के सांस्कृतिक जीवन में बढ़ते पतन के रूप में हैं।

हम नियमों के बढ़ते उल्लंघन के खिलाफ और उन तमाम उत्पीड़ित देशों की संप्रभुता पर जारी व्यापक हमले के खिलाफ लड़ने की शपथ लेते हैं जो साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की ताकतों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, विश्व बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ जैसी उनकी संस्थाओं और साम्राज्यवादी सरकारों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के हमले का शिकार हो रहे हैं।

हम समूची दुनिया में शासक वर्गों द्वारा बढ़ते फासीवादी हमलों, संकीर्णतावादी उन्माद और एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करने की साजिशों के खिलाफ लड़ने की शपथ लेते हैं। खासतौर पर नस्लवाद, यहूदीवाद, इत्यादि का, जिनका कि दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में फासीवादी विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, डटकर मुकाबला किया जाएगा।

हम उन तमाम देशों की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की शपथ लेते हैं जो साम्राज्यवादी, खासतौर पर अमेरिकी साम्राज्यवादी दुराक्रमण के लौह पैरों तले रौंदे जा रहे हैं।

हम साम्राज्यवादियों और उनके आइएमएफ, विश्व बैंक, आदि संगठनों द्वारा तीसरे विश्व को दिए गए तमाम कर्जों को निरस्त करने के लिए लड़ने की शपथ लेते हैं।

हमारा प्रस्ताव है कि हम इराकी जनता के पक्ष में खड़े होकर तब तक दृढ़तापूर्वक संघर्ष करेंगे जब तक कि अमेरिकी और अन्य कब्जाधारी सेनाएं इराक से वापिस नहीं चली जातीं।

हमारा प्रस्ताव है कि हम फिलिस्तीनी और अन्य अरब जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे कि उन्हें उनकी जमीन और संप्रभुता वापिस मिल जाएं; और कि यहूदी और फिलिस्तीनी जनता चैन और अमन के साथ समान अधिकारों से जिए।

हमारा प्रस्ताव है कि हम अफगानिस्तान और दुनिया के तमाम दूसरे देशों से विदेशी सेनाओं की वापसी के लिए तथा समूचे विश्व में अमेरिकी सैन्य अड्डों को बन्द करने के लिए संघर्ष करेंगे।

हमारा प्रस्ताव है कि प्रतिक्रियावादी सरकारों द्वारा कैद किए गए तमाम राजनीतिक बन्दियों की रिहाई के लिए, खासतौर पर उन लोगों की रिहाई के लिए संघर्ष करेंगे जो अमेरिकी साम्राज्यवाद और उनकी कठपुतलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं।

हमारा प्रस्ताव है कि हम आइएमएफ, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसी तमाम बहुपक्षीय संस्थाओं को रद्द करने और दुनिया के उत्पीड़ित देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए लड़ेंगे।

हमारा प्रस्ताव है कि हम साम्राज्यवादियों और दुनिया के उत्पीड़ित देशों के बीच दस्तखत की गई तमाम असमान संधियों और सैन्य समझौतों को फौरन रद्द करने के लिए लड़ेंगे।

हम दृढ़निश्चयी हैं कि दुनिया के सभी राष्ट्र-राज्यों को सर्व सम्पूर्ण संप्रभुता – आर्थिक, राजनीतिक और फौजी – हासिल कर लेंगे। सभी राष्ट्रीयताओं को राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के उनके बुनियादी अधिकार, जहां कहीं भी और किसी भी तरीके से इसका अतिक्रमण किया जा रहा हो, हासिल कर लेंगे।

भारत में, जहां यह अधिवेशन हो रहा है, हमने इन मांगों को लेकर लड़ने का प्रस्ताव किया है कि –

* 'आर्थिक सुधारों', उदारीकरण, निजीकरण और अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीकरण तथा देश में विदेशी पूंजी के निर्बाध प्रवेश का अन्त किया जाए।
* साम्राज्यवादी नमूने के शासन और विकास का अन्त किया जाए। हम लोक-केन्द्रित विकास और सच्चे लोकतंत्र की संस्थाओं के पक्ष में खड़े हैं जिसमें सम्पूर्ण रोजगार और सभी को समान दर्जे की गारन्टी हो। हम काम के अधिकार के लिए लड़ने का प्रस्ताव करते हैं।
* पोटा जैसे अलोकतांत्रिक कानून, हड़तालों और मजदूर संघों पर प्रतिबन्ध, अवैद हत्याएं, यातनाएं, हिरासती बलात्कार, लापता करना, विभिन्न पार्टियों और जन संगठनों पर प्रतिबन्ध, आदि रूपों में जारी राजकीय आतंक का अन्त किया जाए।
* राज्य द्वारा प्रायोजित हिन्दुत्ववादी फासीवाद का अन्त किया जाए, अल्पसंख्यकों के तमाम अधिकारों की हिफाजत की जाए तथा बाबरी मसजिद की तबाही और गुजरात नरमेध के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को सजा दी जाए।
* राष्ट्रीयताओं के आन्दोलनों के खिलाफ सैन्य कार्यवाहियों को खत्म किया जाए। भूटान से सभी भारतीय सेनाओं को वापिस बुलाया जाए जो कि वहां पर आधारित आन्दोलनों को कुचलने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। सभी राष्ट्रीयताओं को आत्मनिर्णय का उनका अधिकार

दे दिया जाए।

* जनता के हथियारबन्द क्रान्तिकारी संघर्ष समेत सभी जनवादी आन्दोलनों के खिलाफ राजकीय आतंक को समाप्त किया जाए। संगठन बनाने के अधिकार और सभी को आजादी से बोलने के अधिकार की मांग करते हैं।
* आमतौर पर साम्राज्यवाद द्वारा और खासतौर पर अमेरिका/इजराएल धुरी द्वारा हमारी सम्प्रभुता के और ज्यादा अतिक्रमण का अन्त किया जाए।
* किसानों पर हमलों का अन्त हो, जो कि सस्ते आयातों की बाढ़; पूंजीनिवेश में कटौती; रियायती कर्जों, बिजली और पानी की समाप्ति; सब्सिडियों में कटौती और जन वितरण प्रणाली की लगभग समाप्ति; और कृषि के निगमीकरण की मारों को झेल रहे हैं।
* शिक्षा का निजीकरण, नौकरियों की सम्भावनाएं खत्म हो जाना, सांस्कृतिक मूल्यों के पतन को बेहद बढ़ावा आदि रूपों में छात्रों और युवाओं पर जारी हमलों का अन्त किया जाए।
* आदिवासी लोगों को हाशिये पर धकेलने के निरन्तर प्रयासों का अन्त किया जाए। सभी बड़ी परियोजनाओं को रद्द कर दिया जाए जिनसे उनका विस्थापन हो रहा है तथा उनके जल, जंगल, जमीन, सम्पत्ति और स्वशासन के अधिकार खतरे में हैं।
* कामगार वर्ग पर हमलों का अन्त किया जाए तथा बढ़ती बेरोजगारी को खत्म किया जाए। मजदूर विरोधी कानूनों को हटाया जाए, वीआरएस को समाप्त किया जाए तथा श्रम का ठेकेदारीकरण आदि को बन्द किया जाए।
* सभी किस्म के जातिवाद तथा छुआछूत के अमानवीय आचरण का अन्त किया जाए। राज्य के सीधे या परोक्ष समर्थन से दलितों पर बढ़ रहे हमलों को तुरन्त रोका जाए। ब्राह्मणवाद, जो कि नव-उदारवादी भूमण्डलीकरण के तहत दोबारा मजबूत हो रहा है, के खिलाफ तमाम उत्पीड़ित जातियों के लोगों के संघर्षों का हम समर्थन करते हैं।
* भूमण्डलीकरण की नीतियों के चलते दस्तकार जातियों और तबकों पर, जो कि भारत की आबादी में अत्यधिक संख्या में हैं, बेहद खराब असर पड़ रहा है। उन्हें कोई विकल्प दिए बिना ही उनकी जीविका को नष्ट किया जा रहा है। इस स्थिति के खिलाफ हम लड़ने का प्रस्ताव करते हैं।
* दलितों, आदिवासियों और अन्य उत्पीड़ित जातियों पर हिन्दुत्ववादी ताकतों के हमलों तथा हिन्दू राष्ट्र के बुरे मंसूबे को पूरा करने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाने की साजिशों को खत्म किया जाए।
* पितृसत्ता के सभी स्वरूपों और भूमण्डलीकरण के इस युग में महिलाओं को माल बनाने वाली बढ़ती प्रवृत्ति का अन्त किया जाए। खासतौर पर महिलाओं की बढ़ती खरीद-फरोख्त और विज्ञापन, पर्यटन, अश्लीलता आदि से महिलाओं के वजूद को खत्म करने वाली बढ़ती प्रवृत्ति का अन्त हो।
* भारतीय विस्तारवाद तथा भारत के शासक वर्गों द्वारा उनके अमेरिकी आकाओं के घनिष्ठ सहयोग से पड़ोसी देशों के साथ धौंस जमाने और समझौतों का अन्त किया जाए।

हम तमाम जनता का आह्वान करते हैं कि बहुराष्ट्रीय/पारराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों का बहिष्कार करे और इस तरह साम्राज्यवादियों और उनके बाजारों को व्यापक नुकसान पहुंचाए। जुझारू जन संघर्षों का निर्माण करे ताकि उन्हें, खासतौर पर अमेरीकी साम्राज्यवादियों की कम्पनियों को हमारे देश छोड़ने पर मजबूर किया जा सके।

हम जनता का आह्वान करते हैं कि दुनिया भर के अमेरिकी सैन्य अड्डों के खिलाफ सख्त प्रतिरोध खड़ा करे। हमारा प्रस्ताव है कि हम तब तक एक निरन्तर जन-विरोध आन्दोलन चलाएंगे जब तक कि अमेरिका और अन्य साम्राज्यवादियों के सैन्य अड्डों को पूरी तरह वापिस नहीं लिया जाता।

हम भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की जनता का आह्वान करते हैं कि 'भूमण्डलीकरण' के नाम से जारी साम्राज्यवादी आक्रमण के खिलाफ लड़ने एकजुट हो तथा दुनिया भर में मेहनतकश लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आओ।

हम जनता का आह्वान करते हैं कि साम्राज्यवादी आक्रमणकारियों, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों का सफाया करे तथा खासतौर पर इराक, अफगानिस्तान और फिलिस्तीन के प्रतिरोधी आन्दोलनों के साथ जीत हासिल करने तक मजबूती से एकताबद्ध हो।

हम जनता का आह्वान करते हैं कि राजकीय आतंक, पोटा जैसे जनवादी कानूनों की खिलाफत करे तथा दुनिया भर में बढ़ते फासीवादी हमले के खिलाफ लड़े।

हम जनता का आह्वान करते हैं कि खासकर गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक जनवादियों द्वारा अतंतोष को कम करने जैसी साम्राज्यवादी साजिशों और षड़यंत्रों में न फंसे, बल्कि एक विशाल व जुझारू आन्दोलन खड़ा करे ताकि साम्राज्यवाद और उसके दुनिया भर में फैले हुए दलालों का सफाया किया जा सके। एक नई व्यवस्था के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए जो कि बराबरी और सभी को इंसाफ की बुनियाद पर खड़ी हो, यानी एक ऐसी दुनिया जो समाजवाद की ओर बढ़ रही हो।

साम्राज्यवाद और तमाम तरह के प्रतिक्रियावाद के खिलाफ दुनिया भर में संघर्षरत जनता के साथ हम घनिष्ठभाईचारा और एकजुटता प्रकट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सांझे दुश्मन, यानी साम्राज्यवाद और उससे जुड़े हुए वर्गों के खिलाफ आम जंगे मैदान खड़े करने में बढ़िया तालमेल हो।

हम, मुम्बई प्रतिरोध 2004 के परचम तले इकट्ठे होने वाले विश्व के संघर्षरत लोग, यह घोषणा करते हैं कि हम आमतौर पर लोगों के सभी मुक्ति आन्दोलनों, खासतौर पर नेपाल, कोलम्बिया, पेरू, फिलिप्पीन्स, बंग्लादेश, तुर्की और भारत के लोगों के आन्दोलनों का सम्पूर्ण समर्थन करते हैं। असली जनवाद के लिए लड़े जा रहे इन जन आन्दोलनों को कुचलने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके छुटभैयों द्वारा अमल सैन्य षड़यंत्रों और दमनकारी नीतियों की हम कड़ी निंदा करते हैं।

विश्व जनता के इस साम्राज्यवाद-विरोधी जमावड़े से हम यह घोषणा करते हैं कि हम अमेरिकी साम्राज्यवाद और उनके स्थानीय दलालों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हम मजबूती से प्रस्ताव करते हैं कि इराक से सेनाओं को वापिस लेने की मांग से जन आन्दोलनों को तेज करेंगे। दक्षिणी अमेरिका में अमेरिका के प्लान-कोलम्बिया और अन्य सैन्य षड़यंत्रों के खिलाफ तथा आमतौर पर दक्षिण एशिया में और खासतौर पर फिलिप्पीन्स और नेपाल में उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष फौजी दखलंदाजियों के खिलाफ हम लड़ेंगे।

18 जनवरी 2004 के इस दिन, आइए हम सब कसम खा लें कि हम एकजुट होकर संघर्ष के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। दुनिया के तमाम शोषित जन समुदायों के लिए हम एक नया शानदार भविष्य बनाएंगे। पहले कदम के तौर पर, हम 20 मार्च को साम्राज्यवादी युद्ध विरोध दिवस मनाएंगे; वह दिन जब अमेरिकी/ब्रितानी बलों ने इराक पर आक्रमण किया था। उस दिन साम्राज्यवादियों के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के साथ साम्राज्यवादी ताकतों और भारत समेत दुनिया भर में उसके दलालों के खिलाफ जुझारू कार्यवाहियां भी की जाएं।

18 जनवरी 2004

हस्ताक्षरित,

एमआर-2004 के 311 घटक संगठनों द्वारा।

छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों की हड़ताल - नेतृत्व की गद्दारी के चलते विफल

1991 से भारत में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भूमण्डलीकरण, निजीकरण व उदारीकरण के नाम से तथा विश्व बैंक व आईएमएफ-निर्देशित ढांचागत समायोजन के नाम से सुधारों पर अमल शुरू किया। इसी नीति पर आज केन्द्र में राजग और राज्यों में अलग-अलग सरकारें अमल कर रही हैं।

पिछड़े देशों के दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें और पार्टियां ऐसी ही नीतियां लागू कर रही हैं जिससे साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मुनाफा मिले और उनके उत्पादों के लिए बाजार खुल जाए। इसी पृष्ठभूमि में उस समय के अविभाजित मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी शिक्षा का व्यावसायीकरण, निजीकरण और सरकारी सहायता में कटौती की नीति शुरू की। इस नीति के तहत कम वेतनों पर ज्यादा शिक्षकों को नियुक्त करना और बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का सब्जबाग दिखाना शुरू किया गया। इसी नीति के तहत 1995 में मध्यप्रदेश सरकार ने 'शिक्षा गारन्टी योजना' लागू की। इसके फलस्वरूप 'शिक्षा गारन्टी गुरूजी' के नाम से नौकरियां अस्तित्व में आईं। इसी मौके पर मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी नियम-1997 के नाम से आदेश जारी करके शिक्षकों को 'शिक्षा कर्मी' बनाया गया। अलग-अलग प्रदेशों में इन्हें अलग-अलग नाम दिए गए। मसलन आन्ध्रप्रदेश में इन्हें शिक्षा वलन्टियर के नाम से पुकारा जाता है। योजना चाहे जो हो लेकिन उसका मतलब एक है – राजस्व घाटे को कम करने के नाम से सरकारी खर्च को कम करना, शिक्षा व चिकित्सा जैसी जनहितकारी सेवा क्षेत्रों को नाम के वास्ते दी जा रही सब्सिडियों में कटौती करना आज दलाल शासक वर्गों की नीतियों का हिस्सा बन चुका है। सरकार इन नीतियों पर "सरल, जवाबदेह और पारदर्शी सुधारों" के नाम से अमल कर रही है ताकि लोगों और बेरोजगार युवाओं को छला जा सके। इस पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षाकर्मियों ने पिछले साल जुलाई-अगस्त महीनों में जो हड़ताल की थी वह बिना किसी नतीजे के ही समाप्त हो गई। न्यूनतम मांगें हासिल करने में भी नाकाम रही। इसकी वजह है राज्य स्तरीय नेतृत्व की गद्दारी जिसने सरकार के अल्टिमेटम के सामने घुटने टेकते हुए हड़ताल वापिस ली।

इस हड़ताल की पृष्ठभूमि में तमाम शोषित और उत्पीड़ित कर्मचारियों को गुणदोषों का सही विश्लेषण करके आवश्यक शिक्षा लेने की जरूरत है।

1995 में अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर सरकार ने यह कहते हुए शिक्षा गारन्टी गुरुजनों और शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति शुरू की कि वह शिक्षा का निचले तबकों तक प्रसार करेगी। कई गांव-पाराओं में कुछ नई शालाएं शुरू की गईं। कांग्रेस सरकार ने अपने प्रचार माध्यमों के जरिए बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया था कि वह हर दिन एक नई शाला खोलकर शिक्षा को लाखों ग्रामीणों और शहरी गरीबों की पहुंच में ला रही है। कुछेक शिक्षाविदों ने इसकी तारीफ करते हुए सभी राज्यों को इसे आदर्श बनाने की हिदायत भी दी थी। नाम अलग होने के बावजूद समान सेवाएं देने वाले शिक्षाकर्मी लगातार घोर अन्याय का शिकार होते आ रहे हैं। पिछले छह सालों में उन्होंने अपनी जायज मांगों को लेकर कई बार हड़ताल की।

सरकार ने शिक्षाकर्मियों को तीन वर्गों में बांटकर निम्न प्रकार के वेतनमान तय किए हैं।

वर्ग - 1	....3,900 रुपए
वर्ग - 2	....3,250 रुपए
वर्ग - 3	....2,700 रुपए

इसी प्रकार शिक्षा गारन्टी गुरूजियों को सरकार पंचायत विभाग के माध्यम से 500 रुपए और 1,000 रुपए का मासिक वेतन दे रही है। प्रदेश भर में 28 हजार शिक्षाकर्मी अलग-अलग शालाओं में कार्यरत हैं। ये लोग सरकार के सामने अपनी यह मांग लगातार उठाते आ रहे हैं कि "समान काम के लिए समान वेतन, समान पद और एक ही विभाग" हो। लेकिन सरकार के कान में आज तक जूं तक नहीं रेंगी। इन्हें पेन्शन, ग्रैट्युटी आदि सुविधाएं भी नहीं हैं। भविष्य निधि की सुविधा भी नहीं। डीए में वृद्धि दर शून्य प्रतिशत है। एक ही शाला में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षकों को सरकार ने अधिक वेतन देते हुए शिक्षाकर्मियों को तो बेगारी मजदूरों से बदतर बनाया है। उनका बेहद शोषण कर रही है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल शिक्षकों के वेतनमान इस प्रकार हैं –

व्याख्याता - श्रेणी-1	5,500-175-9,000
शिक्षक - श्रेणी-2	5,000-125-7,000
सहायक - शिक्षक श्रेणी-3	4,000-100-6,000

इससे शिक्षाकर्मियों ने समान काम के लिए समान वेतन और समान पद व एक ही विभाग की अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार से कई बार गुहार लगाई। कोई परिणाम न निकल पाने से 2003 में उन्होंने अपना संघर्ष तेज कर दिया। उन्होंने मांग की कि उन्हें पंचायत विभाग की बजाए शिक्षा विभाग के कर्मचारी माना जाए। फरवरी 2003 में शिक्षाकर्मियों ने राज्य भर में 16 दिनों तक हड़ताल करके शिक्षण संस्थाओं को ठप्प कर दिया। सभी जिला मुख्यालयों और प्रदेश की राजधानी रायपुर में हड़ताल के दौरान भूख हड़ताल भी जारी रखी। इससे तत्कालीन राज्य सरकार ने इन शिक्षकों की मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने पंचायत विभाग के सचिव एमके रावत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने जुलाई 2003 में शिक्षाकर्मियों पर अपनी सिफारिशें सरकार के सामने पेश कीं।

एमके रावत कमेटी द्वारा प्रस्तावित शिक्षाकर्मियों के वेतनमान

इस प्रकार हैं –

वर्ग-1	...3,900-50-4,900
वर्ग-2	...3,250-40-4,050
वर्ग-3	...2,700-30-3,300

इसमें डीए शून्य प्रतिशत होगा। रावत कमेटी ने ऐसी सिफारिशें कीं जिसमें भविष्य निधि में कटौती होगी और पेन्शन व ग्रैट्यूटी की कोई सुविधा नहीं होगा। अगर शिक्षाकर्मियों की मांगें मान ली जाएं तो सरकार को उन्हें शिक्षकों के बराबर वेतन देने होंगे। इससे सरकार के खजाने में 76 करोड़ रुपए की सेंध पड़ेगी, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन शिक्षाकर्मियों के संगठन ने मांग की कि उनके लिए भी पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते हुए उनके वेतनमानों में संशोधन किया जाए। अगर सरकार पांचवां वेतनमान की सिफारिशें लागू करती है तो उस पर सिर्फ 34 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे सरकार के खजाने पर कोई भारी बोझ नहीं पड़ने वाला है, ऐसा कहकर शिक्षाकर्मियों के संगठन ने सबूत के तौर पर आंकड़े पेश किए। लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को ठुकराते हुए रावत कमेटी की अन्यायपूर्ण सिफारिशें सामने लाईं। इससे नाराज होकर शिक्षाकर्मियों ने जुलाई 23 को रावत कमेटी सिफारिशों के दस्तावेज को आग लगाकर अपना कड़ा विरोध जताया। जिला कलेक्टरों को मांग पत्र सौंप दिए। सरकार द्वारा जारी शिक्षा के व्यापारीकरण के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। एक ही काम करने वाले लोगों को सरकार शिक्षक, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक आदि नाम देकर अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर, उन्हें असमान वेतन देते हुए बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसका विरोध करते हुए शिक्षाकर्मियों ने अपनी एकसूत्रीय मांग – 'समान काम के लिए समान वेतन' मजबूती से सामने लाई।

जुलाई 2003 में हड़ाताल शुरू कर दी गई। सभी जिला मुख्यालयों में बारी-बारी से भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। पहली बार शिक्षाकर्मियों के समर्थन में छात्रों और उनके अभिभावकों ने रैलियां निकालीं। उनकी मांगें ये थीं –

1) समान काम को समान वेतन चाहिए,
2) वार्षिक वेतन में वृद्धि होनी चाहिए,
3) हमारी नौकरियों का नियमितीकरण किया जाए,
4) वेतन-भत्ते का पहले ही भुगतान किया जाए,
5) हमें शिक्षा विभाग और आदिवासी कल्याण विभाग के कर्मचारियों में शामिल कर दिया जाए।

इन मांगों के साथ-साथ पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, पेन्शन व डीए की सुविधा देने आदि मांगें भी करते हुए उन्होंने राज्य भर में हड़ताल तेज की। शिक्षाकर्मियों की 'समान काम के लिए समान वेतन' की मांग का समर्थन करते हुए 6 जिलों में 7 जिला पंचायतों और 16 जनपद पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किए। कर्मचारियों और मजदूरों के अत्यधिक संगठनों ने इस हड़ताल के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया। शिक्षाकर्मियों के परिवारजनों के साथ-साथ कई गांव-शहरों के आम लोगों और छोटे बच्चों ने भी इनके न्यायिक संघर्ष का समर्थन करते हुए रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन किया। चूंकि प्रदेश भर में कई जिलों में शिक्षाकर्मियों ने लगातार कई दिनों तक भूख हड़ताल की, इसलिए कइयों की तबियत बुरी तरह बिगड़ गई। 11,900 शिक्षाकर्मियों को अस्पतालों में दाखिल किया गया। शिक्षाकर्मियों ने अपने इतिहास में पहली बार बेहद मजबूत संकल्प के साथ यह व्यापक हड़ताल की। उन्होंने अपने संघर्ष के प्रति सभी तबकों के लोगों का समर्थन हासिल किया। व्यापारियों के समूहों ने खुद ही इस हड़ताल के समर्थन में सभी जिला मुख्यालयों में बन्द आयोजित किया। 16 अगस्त को बीजापुर बन्द, 20 अगस्त को जगदलपुर बन्द रखा गया। नारायणपुर, दन्तेवाड़ा, कांकेर, बड़गांव, पखांजूर, धमतरी, जगबरा इत्यादि छोटे-बड़े विकासखण्ड मुख्यालयों समेत लगभग सभी जिला मुख्यालयों में बन्द का पालन किया गया। किसानों ने भी प्रदर्शन किए। छात्रों ने भी इनकी हड़ताल के समर्थन में बड़े पैमाने पर आन्दोलन किया। सरकार ने एक तरफ चौमुखी विकास लाने, आदिवासी इलाकों में विशेष पैकेज (बस्तर पैकेज और सरगुजा पैकेज) की घोषणा करके आश्रमशालाओं के जरिए साक्षरता में वृद्धि लाने आदि प्रचार तो बढ़-चढ़कर किया है, दूसरी तरफ शिक्षाकर्मियों की जायज मांगों को ठुकराकर अपना दलाल चरित्र का नंगा प्रदर्शन किया। रावत कमेटी द्वारा अवास्तविक और बेतुके वेतनमानों की सिफारिशें करवाकर सरकार ने हड़ताल को लौह पैरों से रौंदने की कोशिश की। पिछले साल 25 जुलाई से शुरू हुई शिक्षाकर्मियों की हड़ताल को अजीत जोगी मंत्रीमण्डल ने सहानुभूति से देखने की बजाए दमन का सहारा लिया। शिक्षा मंत्री ने अखबारों में एक लेख लिखते हुए भद्दी तर्क पेश किए कि शिक्षाकर्मियों को हड़ताल करने का अधिकार ही नहीं है और वे शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि पंचायत विभाग के दिहाड़ी मजदूर हैं। उसने शिक्षाकर्मियों के साथ किसी तरह की बातचीत की संभावना से इनकार करके तानाशाहीपूर्ण बयान दिए। दैनिक भास्कर, नव भारत जैसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख दैनिक अखबारों ने शिक्षाकर्मियों की हड़ताल को अनुचित और बेतुकी ठहराते हुए उन्हें कई हिदायतें दे डालीं – जैसे कि उन्हें तमिलनाडु मुख्यमंत्री जयललिता की कार्यवाही से सबक लेना चाहिए जो उसने वहां के सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की; सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को शिक्षाकर्मियों को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें उसने हड़ताल को असंवैधानिक करार दिया; अधिक वेतनों की मांग नहीं करनी चाहिए बल्कि सरकार जो कुछ देती है उतना ही ले लेना चाहिए; समान काम के लिए समान वेतन की मांग बुद्धिसंगत नहीं है, इत्यादि। ऐसे जहरीले बयानों से अखबारों ने अपनी प्रतिक्रियावादी विचारधारा का खुला प्रदर्शन किया। पहली बार ऐसा हुआ कि इस हड़ताल के प्रति हर पार्टी और हर तबके ने अपना रवैया स्पष्ट किया। दरअसल चूंकि वह चुनावों की पूर्वसंध्या थी, इसलिए हरेक बुर्जुवाई पार्टी की यह मजबूरी थी कि वे अपना रवैया स्पष्ट करकर ही मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर सकती थीं।

कांग्रेस व भाजपा के प्रभाव में रहे शिक्षाकर्मियों के राज्य स्तरीय नेतृत्व ने जनता के व्यापक समर्थन के बल पर अपना संघर्ष दृढ़ता एवं जुझारू ढंग से जारी नहीं रखा। ज्यों ही अजीत जोगी ने 19 अगस्त को हड़ताल वापिस नहीं लेने पर शिक्षाकर्मियों को नौकरी से हटाने का अल्टिमेटम दिया, उसके दो ही दिन बाद यानी शिक्षाकर्मियों के

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, जो तब तक गंभीर भाषणबाजी करते नहीं थकता था, ने घुटने टेक दिए और हड़ताल वापिस लेने की घोषणा की। लगभग 25 दिनों तक दृढ़तापूर्वक संघर्ष करने के बाद बिना किसी वाजिब समझौते के ही इस प्रकार अपमानजनक ढंग से हड़ताल को वापिस लने के फैसले से अलग-अलग जिलों के निचले स्तर के संगठन सहमत नहीं थे। लेकिन ईमानदार व सुदृढ़ नेतृत्व के अभाव में उन्होंने अपना आन्दोलन अधूरा ही समाप्त किया। लेकिन आम शिक्षाकर्मियों के मन में सरकार के मनमाने शोषण और तानाशाहीपूर्ण रवैये के प्रति तीखी नफरत है। वे अपने नेतृत्व से इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि उसने उन अनेक कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जिन्हें सरकार ने हड़ताल में सक्रिय भाग लेने के कारण नौकरियों से बरखास्त किया।

हड़ताल के सबक

हड़ताल को राज्य भर में सभी तबकों से समर्थन प्राप्त हुआ। बच्चों, छात्रों, आम लोगों, व्यापारियों आदि ने इस हड़ताल के समर्थन में रैलियों, प्रदर्शनों और बन्द में भाग लिया। अविभाजित बस्तर के विशाल किसान समुदाय शिक्षाकर्मियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। चेरपाल में 3 हजार, बासागूडा में 4 हजार और कांकेर जिले के कुछ शहरों में कई हजार किसानों ने शिक्षाकर्मियों के संघर्ष के समर्थन में अगस्त के तीसरे सप्ताह में रैलियां निकालीं। जनता के इतने व्यापक समर्थन के बावजूद इस प्रकार नेतृत्व का हड़ताल को वापिस लेना किसी भी कर्मचारी के गले नहीं उतरा। लेकिन विकल्प के अभाव में वे अपने नेतृत्व को कोसते हुए ही काम में लग गए।

1 दिसम्बर को हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में नकारात्मक मतदान से भाजपा विजयी हुई। रमणसिंह की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ। चुनाव के पहले वोट बटोरने के हथकण्डे के तौर पर शिक्षाकर्मियों की 'समान काम के लिए समान वेतन' की मांग का समर्थन कर चुकी भाजपा सत्ता में आने के बाद महज 100 रुपए वेतन बढ़ाकर हाथ झाड़ लिए। शिक्षाकर्मियों की प्रमुख मांग को ठुकरा दिया। नौकरी से बरखास्त किए गए बिलासपुर के शिक्षाकर्मियों को भाजपा सरकार ने भी बहाल नहीं किया और वे आज भी अदालतों का चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इससे सभी श्रेणियों के शिक्षकों और अन्य विभागों के कर्मचारियों को अब तक यह बात समझ में आ चुकी होगी कि कांग्रेस और भाजपा में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। भाजपा भी साम्राज्यवादियों द्वारा निर्देशित उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नीतियों पर अमल करने वाली पार्टी ही है। इतना ही नहीं, भाजपा के सत्ता में आने के एक महीने के अन्दर ही बाल्को का पूर्ण निजीकरण करने का फैसला लिया गया है। जहां अजीत जोगी के शासन में अकेले रायपुर में ही 20 निजी विश्वविद्यालय कुकुरमुत्तों की तरह उग आए थे, तो वहीं अब भाजपा के शासन में शिक्षा का भगवाकरण के साथ-साथ व्यापारीकरण की प्रक्रिया तेजी पकड़ने जा रही है। शिक्षा के व्यापारीकरण और शिक्षा विभाग के कोश में कटौती करने में भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस, संशोधनवादी भाकपा व माकपा, तेलुगुदेशम पार्टी सभी की नीति एक है।

भूमण्डलीकरण की आर्थिक नीतियों के तहत एक तरफ शिक्षा का व्यापारीकरण और दूसरी ओर इन सभी नीतियों के पक्ष में सर्वोच्च अदालतों के फैसलों को समझकर आने वाले दिनों में सभी विभागों के कर्मचारी और शिक्षाकर्मी अपने संघर्षों को दृढ़ता से जारी रखेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। शिक्षाकर्मी पिछले 7 सालों से अपने नेतृत्व पर विश्वास रखकर जब-जब उसने हड़ताल का अह्वान किया तब-तब हड़ताल में भाग लेते आ रहे हैं। लेकिन मुख्य नेतृत्व ने हर बार खोखले अश्वासनों से दिग्भ्रमित होकर या धमकियों से डरकर हड़ताल को वापिस लेकर शिक्षाकर्मियों के लड़ाकूपन पर पानी ही फेरा है। नौकरियों को गंवाने पड़ सकने का डर छोड़कर अगर आप विशाल जन समुदायों के समर्थन से संघर्ष में उतरेंगे तो सरकार को झक मारकर उतर आना पड़ेगा। आपकी हड़ताल के प्रति राज्य भर में जो जन समर्थन हासिल हुआ, उससे साफ होता है कि जनता आपके साथ है। सत्ता में चाहे जो भी पार्टी आए उन सभी का चरित्र एक है, यह बात आप ध्यान में रखें। तमाम जनता और अन्य कर्मचारियों का समर्थन हासिल कर लेते हुए, नेतृत्व के हाथों दोबारा धोखा न खाते हुए आप आगे बढ़ें। हम आशा करते हैं कि आप अपनी जायज मांगों को लेकर दृढ़ता से लड़कर सरकार को सबक सिखा देंगे। ❑

(.... पृष्ठ 18 का शेष)

हमारी पार्टी तहेदिल से समर्थन करती है। हमारे संघर्ष के इलाकों में लोगों ने पिछले साल आपके संघर्ष के समर्थन में रैलियां निकालीं और कई अन्य विरोध कार्यक्रम भी चलाए। आपके प्रति यहां के किसानों ने जो एकजुटता व आत्मीयता का प्रदर्शन किया, वाकई काबिले तारीफ रहा। आप लुटेरे नेताओं और लुटेरी पार्टियों के खोखले आश्वासनों पर यकीन करना छोड़ दें। सरकारों की धमकियों और पुलिसिया दमन से डरना भी छोड़ दें। आप सिर्फ मजदूर-किसान और अन्य शोषित तबकों के लोगों पर भरोसा करें जो आपकी जायज मांगों का समर्थन करते हैं। तमाम शिक्षक जगत् व छात्रों के साथ एकजुटता कायम करें। आपको यह बात भी खासतौर पर याद रखनी होगी कि कोई भी संघर्ष तभी सफल होगा, जब उसका नेतृत्व सही व सक्षम हो। इसलिए आप अपने गद्दार, बिकाऊ व समझौतापरस्ती नेताओं को दरकिनार करें। सही व जुझारू नेतृत्व को चुन लें और आन्दोलन को पूरी शक्ति के साथ चलाएं। हम और हमारे दण्डकारण्य की समूची शोषित जनता आपके साथ हैं।

(कोसा)

सचिव,

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्सवार]

मांगें पूरी होने तक संघर्ष करो ! **चुनावों का बहिष्कार करो !!**

शिक्षाकर्मियो व गुरुजियो ! समझौतापरस्ती नेतृत्व को ठुकराकर जुझारू संघर्ष का रास्ता अपनाएं !

दोस्तो !

आज देश में हर तरफ "फील गुड फैक्टर" का भ्रम फैला हुआ है। भाजपा ढिंढ़ोरा पीट रही है कि देश के चारों ओर खुशहाली छाई हुई है। लेकिन यह दावा कितना झूठा है, यह समझने के लिए सिर्फ शिक्षाकर्मयों और शिक्षा गारन्टी गुरूजियों की हालत पर नजर डालना काफी होगा। छत्तीसगढ़ में 28 हजार शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं। ये कई सालों से कम वेतन पर काम कर रहे हैं और सरकारों द्वारा लगातार उपेक्षा व वायदाखिलाफी का शिकार होते आ रहे हैं। इन्होंने अपनी एक सूत्रीय मांग – "समान कार्य समान वेतन" – को लेकर कई बार आन्दोलन चलाया। इनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। जब-जब इन शिक्षाकर्मियों ने कोई आन्दोलन चलाया या कोई जुलूस-धरना आयोजित किया, हर बार इन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ीं और बर्बर दमन का शिकार होना पड़ा।

शिक्षाकर्मियों के आन्दोलन के साथ उनके अक्षम और समझौतापरस्ती नेताओं ने हर बार गद्दारी की। संघर्ष को जुझारू तरीके से आगे बढ़ाने की बजाए सरकार की धमकियों या कोरे आश्वासनों के सामने इनके नेतृत्व ने हर बार घुटने टेक दिए। पिछले साल शिक्षाकर्मियों ने एक व्यापक आन्दोलन चलाया था। प्रदेश के हर जिले में शिक्षाकर्मी आमरण अनशन पर चले गए थे। समाज के हर तबके ने इनके आन्दोलन का तहेदिल से समर्थन किया था। चूंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक थे, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी शिक्षाकर्मियों के संघर्ष का समर्थन करके बहती गंगा में हाथ धोए थे। भाजपा ने ताल ठोंककर ऐलान किया था कि उसकी सरकार बनते ही शिक्षाकर्मियों की सारी समस्याएं पूरी कर ली जाएंगी। आमरण अनशन पर बैठे शिक्षाकर्मियों को पुलिस ने उठा-उठाकर जबरन अस्पतालों में भर्ती कराया और गिरफ्तार किया। सरकार ने शिक्षकर्मियों को नौकरी से बरखास्त करने की धमकी दी, जिसके आगे शिक्षाकर्मियों का नेतृत्व झुक गया और हड़ताल वापिस ली। और इस प्रकार 28 हजार शिक्षाकर्मियों के साथ जबर्दस्त विश्वासघात किया।

चुनाव सम्पन्न हुए। अपनी जन-विरोधी नीतियों का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। कांग्रेस को हराने वालों में शिक्षाकर्मी भी शामिल थे जो अजीत जोगी के तानाशाही शासन से पुरी तरह नाराज थे। कई शिक्षाकर्मियों की यह उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार बनेगी तो उनके साथ न्याय किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भीख के बराबर, वेतन में सिर्फ 100 रुपए की बढ़ोत्तरी करके रमण सिंह सरकार ने हाथ झाड़ लिए। ऊपर से यह हिदायत भी दी कि शिक्षाकर्मी धैर्य रखें। जिन लोगों को छह-छह, सात-सात महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को सालों से मेहनत करने के बावजूद समान वेतन नहीं मिल रहा है और जिन लोगों का पेट जल रहा है उन लोगों को रमण सिंह "धैर्य रखने" का पाठ पढ़ा रहा है। गौरतलब है कि 'धैर्य रखने' की हिदायत भी आगमी संसदीय चुनाव के मद्देनजर ही दी जा रही है। इससे फिर एक बार साबित हो गया कि भाजपा और कांग्रेस चोर-चोर मौसेरे भाई जैसी ही हैं। दोनों की नीतियों में कोई फर्क नहीं हैं। दोनों ही पार्टियां जमींदारों और बड़े पूंजीपतियों की हैं।

अभी-अभी प्रदेश के 7 हजार शिक्षा गारन्टी गुरूजियों ने अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। कुल 5,700 शालाओं में पढ़ाने वाले इन गुरूजियों की मांग है कि उनका नियमितिकरण किया जाए। प्रदेश में कुल ढाई लाख बच्चों को पढ़ाने वाले इन गुरूजियों की स्थिति शिक्षाकर्मियों से भी बदतर है। बहुत कम वेतन पर ये लोग कई सालों से काम कर रहे हैं। इन्होंने सरकार को 10 फरवरी तक नियमितिकरण की मांग पूरी न करने से प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जाने का अल्टिमेटम दिया था, इसके बावजूद भी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। इससे उन्हें आन्दोलन शुरू करना पड़ा।

शिक्षाकर्मियो और गुरूजियो !

दरअसल कांग्रेस, भाजपा इत्यादि लुटेरी पार्टियां विश्व बैंक जैसी साम्राज्यवादी संस्थाओं द्वारा निर्धारित नीतियों पर चल रही हैं। सभी सरकारें शिक्षा पर खर्च में कटौती करके शिक्षा के सम्पूर्ण निजीकरण की दिशा में चल रही हैं। इसके तहत ही निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को धड़ल्ले से इजाजत दी जा रही है। सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाकर शिक्षा गारन्टी योजना और शिक्षाकर्मियों के नाम से अनियमित नियुक्ति करना भी विश्व बैंक की शर्तों का हिस्सा ही है। शिक्षा ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र का निजीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सभी सरकारी कम्पनियों को दलाल पूंजीपतियों या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को औने-पौने दामों पर बेचा जा रहा है। जन कल्याण के कार्यक्रमों पर खर्च में कटौती की जा रही है। हर क्षेत्र में नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई। कम्पनियों में मजदूरों की छंटनी बड़े पैमाने पर की जा रही है। यह पूरा विश्व स्तर पर चल रहा है जो कि साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण का हिस्सा है। दरअसल, आपकी समस्या एक बहुत बड़े दुष्चक्र का हिस्सा है जिसके पीछे साम्राज्यवाद के साथ-साथ हमारे देश के जमींदारी व दलाल पूंजीपति वर्ग खड़े हैं। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि सिर्फ अपनी मांगों तक ही सीमित न रहें, बल्कि समाज में मौजूद सभी मूलभूत समस्याओं के साथ जोड़कर देखें। आज सामंतवाद, दलाल पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को जड़ से खत्म करने वाले एक व्यापक संघर्ष के बिना किसी भी समस्या का स्थाई हल नहीं हो सकता।

आपकी मांगें बिलकुल जायज हैं। आप लोगों के संघर्षों का

(शेष पृष्ठ 17 पर ....)

(.... अन्तिम पृष्ठ का शेष)

दुश्मन पर उसके अपने ही अड्डे पर चोट करके हमारे बहादुर जन हथियारबन्द बलों ने शासक वर्गों की उन साजिशों को धक्का लगाया जिन्हें वे देश में जारी जनयुद्ध को कुचलने के लिए एक के बाद एक योजना बनाते हुए अंजाम दे रहे हैं। शासक वर्ग देश भर के नौ राज्यों के पुलिस बलों और देश में मौजूद एक तिहाई से ज्यादा सीआरपी बलों का इस्तेमाल करते हुए ज्वाइन्ट ऑपरेशनल कमाण्ड (जेओसी) की अगुवाई में अपना हमला जारी रखे हुए हैं। पिछले 1 अक्टूबर को आन्ध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री और विश्व बैंक का दलाल चन्द्रबाबू नायुडू पर एक पीजीए ने एक बहादुराना हमला किया था जो उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी आक्रमण के खिलाफ लगाया गया पहला बड़ा धक्का था। क्रान्तिकारी आन्दोलन पर क्रूर दमन चलाने में चन्द्रबाबू सबसे आगे खड़ा है। दोनो पार्टियों की केन्द्रीय कमेटियां इस साम्राज्यवादी दलाल और फासीवादी तानाशाह, जो इस हमले में बाल-बाल बच गया था, पर पीजीए द्वारा किए गए वीरोचित कार्यवाही की प्रशंसा करती हैं।

उड़ीसा में रायगडा, गजपति, मलकनगिरी, कोरापुट, मयूरभंज, नुआपारा, बारागढ़, सम्बलपुर, जगतसिंगपुर और सुन्दरगढ़ जिलों में भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] और एमसीसीआइ के नेतृत्व में जारी सामन्तवाद-विरोधी संघर्षों के खिलाफ व्यापक पुलिस बलों को तैनात किया गया। झूठी मुठभेड़ों में संघर्षशील किसानों की हत्या की जा रही है। पीपुल्स वार और एमसीसीआइ के कई कॉमरेडों को क्रमशः मयूरभंज और सुन्दरगढ़ जिलों में जेलों में कई सालों से बन्दी बनाकर रखे गए हैं। हाल ही में बासाधारा इलाके के गुडारी गांव में दो किसानों की हत्या कर दी गई। पिछले एक साल के दौरान तीन दक्षिणी जिलों से एक हजार से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जा चुका है। कोरापुट एक मुख्य केन्द्र है जहां से दुश्मन आन्ध्र के ग्रो-हाउण्ड्स और छत्तीसगढ़ के विशेष पुलिस बलों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाकर इन तमाम कार्यवाहियों का दिशा-निर्देश कर रहा है। उड़ीसा सरकार ने आन्ध्र की पुलिस को उड़ीसा के अन्दर सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी अभियान चलाने की इजाजत दी है और उड़ीसा पुलिस को आन्ध्र के ग्रे-हाउण्ड्स बलों द्वारा प्रति-क्रान्तिकारी कार्यवाहियों में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कोरापुट और अन्य जिलों की उत्पीड़ित जनता ने दुश्मन की इस शर्मनाक पराजय से बेहद खुशियां मनाईं जो उसे आए दिन बेहद प्रताड़ना और अकथनीय अत्याचारों का शिकार बनाया करता था। इन कार्यवाहियों की तैयारियों और उनके संचालन में अपनी सक्रिय मदद देने वाली जनता की तमन्नाओं को कोरापुट के ये हमले प्रतिबिम्बित करते हैं।

जनता के सामने दुश्मन से हथियार छीनकर खुद को हथियारबन्द बनाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है ताकि जनयुद्ध को अन्तिम विजय की मंजिल तक पहुंचाया जा सके। इस दिशा में कोरापुट एक महत्वपूर्ण लम्बा कदम है। यह हमारी दोनों पार्टियों की गुरिल्ला शक्तियों और हमारे देश के क्रान्तिकारी जन समुदायों में जबर्दस्त विश्वास बढ़ाता है और उन्हें इस तरह की कार्यवाहियों को बड़े पैमाने पर करने की प्रेरणा देता है ताकि गुरिल्ला फौजों को मजबूत किया जा सके और आने वाले दिनों में उन्हें जन मुक्ति सेना में तब्दील किया जा सके।

पाठकों से अपील

- *कुछ अनिवार्य कारणों से 'प्रभात' के इस अंक के प्रकाशन में काफी देरी हुई, इसके लिए हमें खेद है।*
- *हम सभी जिम्मेदार पाठकों एवं पार्टी कमेटियों के साथियों से विनम्रता से आग्रह करते हैं कि 'प्रभात' के पैसे नियमित रूप से भेजने का कष्ट करें। 'प्रभात' के आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े होने में आपके सहयोग की बेहद जरूरत है।*

- सम्पादकमण्डल

हम, भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] की केन्द्रीय कमेटी और एमसीसीआइ की केन्द्रीय कमेटी, पीजीए के उन बहादुर छापामारों का फिर एक बार क्रान्तिकारी अभिनन्दन करते हैं जिन्होंने बोल्शेविक दृढ़ संकल्प, क्रान्तिकारी दिलेरी और मौत से न घबराने वाली वीरता एवं साहस के साथ कोरापुट में एक साथ जवाबी हमलों के सिलसिले को अंजाम दिया। हम उन क्रान्तिकारी जन समुदायों का भी लाल अभिनन्दन करते हैं जिन्होंने कई तरीकों में छापामारों का सहयोग किया था ताकि इस कार्यवाही को सफल बनाया जा सके।

हम जनता को चौकन्ना रहने का आह्वान करते हैं क्योंकि हथियारबन्द छापामारों का मुकाबला करने से डरने वाले भाड़े के पुलिस बल कायरों की तरह निहत्थे आम लोगों पर बर्बरतापूर्ण हमले कर सकते हैं। दुश्मन के बलों द्वारा तीखे किए गए दमन अभियान का मुकाबला जनता को कई अन्य कोरापुट पैदा करके तथा दुश्मन में उसके मुख्यालय में चैन की नींद सोने न देकर करना चाहिए।

प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग खासतौर पर आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हथियारबन्द संघर्ष के इलाकों में हजारों अर्ध सैनिक बलों को तैनात करके क्रान्तिकारी आन्दोलन को खून की नदियों में डुबो देने की साजिश रच रहे हैं। इस तरह वे तथाकथित लोकतंत्र के नाम पर होने जा रहे चुनावों की नौटंकी के खिलाफ जन प्रतिरोध को खत्म करना चाहते हैं। हम जनता और पीजीए/पीएलजीए के योद्धाओं का आह्वान करते हैं कि दुश्मन के दमन अभियान का हिम्मत के साथ मुकाबला करें और हरा दें तथा दुश्मन के खिलाफ सफल कार्यवाहियों को अंजाम दें जैसे कि कोरापुट में पीजीए छापामारों ने करके दिखा दिया है।

केन्द्रीय कमेटी
भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार]

केन्द्रीय कमेटी
एमसीसीआइ

कोरापुट में पीजीए के शानदार हमलों की प्रशंसा करो !

दुश्मन के प्रतिक्रियावादी बलों से हथियार छीनकर जन बलों को हथियारबन्द बनाओ !

10 फरवरी 2004

भारत में जमींदारी, साम्राज्यवादी और दलाल नौकरशाही पूंजीवादी वर्गों के शोषणकारी बन्धनों से हमारे देश को मुक्त करने के लक्ष्य से जारी माओवादी जनयुद्ध के इतिहास में 6 फरवरी 2004 का दिन एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में लाल अक्षरों में अंकित होगा। उस दिन पीजीए के विशेष बलों ने केन्द्रीकृत सैन्य कमाण्ड की अगुवाई में कोरापुट जिले में एक साथ 10 जगहों पर हमले किए जिससे जिले की मशीनरी पूरे एक दिन तक ठप्प हो गई। भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] और एमसीसीआइ की केन्द्रीय कमेटियां बहादुर छापामारों बलों द्वारा किए गए इन वीरतापूर्ण हथियारबन्द हमलों की यह कहकर प्रशंसा करती हैं कि देश में जारी जनयुद्ध में यह एक नया मील का पत्थर है। केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों, आंध्र के ग्रे-हाउण्ड्स बलों और उड़ीसा के विशेष पुलिस बलों द्वारा जारी भीषण घेराव-दमन अभियानों हासिल और संख्या की दृष्टि से काफी मजबूत दुश्मन के भाड़े के बलों को भी जनता की वह ताकत – जो संख्या की दृष्टि से कमजोर पर मजबूत इरादों वाली, निडर और राजनीतिक रूप से सक्रिय हो – दुश्मन के कमजोर बिन्दुओं की ठोस पहचान करके, अचूक योजना बनाकर और उसे बिजली सी तेजी से दुश्मन को अंचम्भे में डालने के नियम के तहत बढ़िया ढंग से लागू करते हुए जबर्दस्त धक्के लगा सकती है।

छापामारों ने न सिर्फ अलग-अलग हमलों को अंजाम दिया, बल्कि तीसरे बटालियन में मौजूद विशेष पुलिस बलों पर छापामार हमले करके उन्हें वहां से हिलने नहीं दिया ताकि पीजीए की अन्य टुकड़ियां शहर के अन्य जगहों पर अपने हमलों को जारी रख सकें।

भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] और एमसीसीआइ की केन्द्रीय कमेटियों द्वारा जारी संयुक्त बयान

के बीचोंबीच ही और उनका मुकाबला करते हुए ही क्रान्तिकारी जनता की सक्रिय मदद से इन कार्यनीतिक जवाबी हमलों को अंजाम दिया गया।

दुश्मन से हथियार छीनकर पीजीए/पीएलजीए की यूनिटों को हथियारबन्द बनाने की दोनों पार्टियों की केन्द्रीय कमेटियों की सांझी समझ के मुताबिक ही भाकपा (मा-ले) [पीपुल्स वार] के केन्द्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) ने इन हमलों का फैसला लिया था। पीजीए की दो विशेष कम्पनियों ने ये हमले किए। जिला मुख्यालय कोरापुट में दुश्मन के सात अड्डों पर एक साथ किए गए इन हमलों में पीजीए को कार्यनीतिक तौर पर शानदार कामयाबी हासिल हुई। ये अड्डे थे – जिला शस्त्रागार/पुलिस मुख्यालय, शहरी एवं ग्रामीण पुलिस थाने, एसपी का दफ्तर, जिला कोशागार, जिला जेल, उड़ीसा विशेष सशस्त्र बलों की तीसरी बटालियन और उसी जिले के तीन पुलिस थाने (कक्किरिगम्मा, नारायणपट्ना, डिप्यूटी एसपी का दफ्तर व लक्ष्मीपुरम थाना)। इन ठिकानों पर किए गए इन हमलों से छापामार बलों के दावपेंचों जो कॉमरेड माओ की बताई फौजी लाइन पर अधारित आधारित हैं, की अहमियत साफ हो जाती है कि दुश्मन की अत्यधिक मजबूत स्थिति में भी लड़ाई की जाए। इन हमलों ने दिखा दिया है कि बेहतर शस्त्रास्त्रों से लैस, बढ़िया प्रशिक्षण पीजीए की एक अन्य टुकड़ी ने कोलाब स्थित सीआरपीएफ की बटालियन से आने वाली सड़क की नाकेबन्दी कर दी, जो कि शहर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर था। जब केन्द्रीय बलों ने शहर में दुश्मन के अड्डों के बचाव में आगे बढ़ने की कोशिश की तो छापामारों ने एक ट्रक को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया जिसमें ये भाड़े के बल आ रहे थे। इस विस्फोट से दो भाड़े के जवान मौके पर ही मारे गए जबकि तीन अन्य घायल हो गए। इससे सीआरपीएफ को दुम दबाकर पीछे हटना पड़ा और पीजीए की टुकड़ियां शहर में हमलों का सिलसिला सुचारू रूप से चलाकर सकुशल पीछे हट गईं। पीजीए की तीन अन्य टुकड़ियों ने जिले के तीन अन्य पुलिस थानों को कब्जे में लेकर पीजीए बलों की वापसी के लिए रास्ता साफ कर दिया। इन्होंने इन थानों से सारे हथियार और गोलियां छीन लीं। इस प्रकार इन हमलों की बदौलत 500 से ज्यादा अलग-अलग किस्म के हथियार और 25 हजार से ज्यादा कारतूस पीजीए के हाथ लगे। हमलों के दौरान एक सीआरपीएफ का जवान मारा गया और एक जेल अधिकारी घायल हो गया। छापामार बलों को एक भी नुकसान नहीं हुआ।

विशेष रूप से प्रशिक्षित प्रति-क्रान्तिकारी कैम्पों के बीचोंबीच ही

(शेष पृष्ठ 19 पर....)